अवध की आवाज

www.avadhkaawaz.com

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक समाचार पत्र राजधानी लखनऊ उत्तर प्रदेश से प्रकाशित

वर्ष–12 अंक–84 R.N.I.- UPHIN/2012/45127 लखनऊ शुक्रवार 26 जुलाई 2024 पृष्ठ – 4 मूल्य–3 रूपया

संक्षिप्त समाचार

संजय निषाद ने की सीएम योगी से मुलाकात, अधिकारियों की शिकायत के साथ बेटे सरवन निषाद के लिए मांगी सुरक्षा

लखनऊ। यूपी संगठन और सरकार की में आंतरिक कलह जारी है। इस बीच बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के नेता लगातार सीएम योगी से अफसरों की मनमानी की शिकायत कर रहे हैं। गुरुवार को निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद ने सीएम योगी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने सीएम से अधिकारियों की शिकायत की है। कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि मुख्यमंत्री अफसरों की मनमानी के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि अफसरों के न सुनने का असर चुनाव पर पड़ता है। अफसरों के कामकाज पर अपने बयानों में संजय निषाद लगातार हमलावर रहे हैं। इसके साथ ही संजय निषाद ने अपने बेटे की सुरक्षा हटाए जाने पर भी सीएम योगी से बात की। साथ ही फिर से सुरक्षा प्रदान करने को कहा है। बता दें कि उनके बेटे और बीजेपी विधायक सरवन निषाद ने सुरक्षा को लेकर सीएम को पत्र लिखा था।

ऋषि का सद्साहित्य छात्र-छात्राओं को नैतिक शिक्षा प्रदान करता है' : उमानंद शमा

लखनऊ। गायत्री ज्ञान मंदिर इंदिरा नगर, लखनऊ के विचार क्रान्ति ज्ञान यज्ञ अभियान के अन्तर्गत ''एस. आर.वी. आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हॉस्पिटल गौरव विहार, मल्हौर रोड, गोमती नगर लखनऊ'' के केन्द्रीय पुस्तकालय में गायत्री परिवार के संस्थापक युगऋषि पं. श्रीराम शर्मा आचार्य द्वारा रचित सम्पूर्ण 79 खण्डों का 415वाँ ऋषि वांड्मय की स्थापना कार्यक्रम सम्पन्न हुआ। उपरोक्त साहित्य गायत्री परिवार की सक्रीय कार्यकर्ता जे.बी. श्रीवास्तव एवं रेणुका श्रीवास्तव ने अपने पूर्वजों की स्मृति में के लिए भेंट किया तथा सभी छात्र–छात्राओं एवं चिकित्सकों को (हिन्दी) अखण्ड ज्योति पत्रिका भेंट की। इस अवसर पर वाङ्मय स्थापना अभियान के मुख्य संयोजक उमानंद शर्मा ने कहा कि ''ऋषि का सद्साहित्य छात्र–छात्राओं को नैतिक शिक्षा प्रदान करता है'' श्रीमती रेणुका श्रीवास्तव ने भी अपने विचार व्यक्त किये, संस्थान के प्राचार्य प्रो0 (डॉ.) सतीश चन्द्र तिवारी, ने धन्यवाद ज्ञापन व्यक्त किया। इस अवसर पर उमानंद शर्मा, सर्वश्री, देवेन्द्र सिंह, विजय, रेणुका श्रीवास्तव, जे.बी. श्रीवास्तव एवं संस्थान के प्राचार्य प्रो. (डॉ.) सतीश चन्द्र तिवारी डॉ0 सुबोध कुमार पाण्डेय, डॉ. पूजा पाठक, विभागाध्यक्ष चिकित्सकगण एवं छात्र–छात्रायें मौजूद थे।

मेरठ मंडल के जनप्रतिनिधियों से सीएम ने की बैठक,

विधायक नंद किशोर गुर्जर बोले, मैं विधायक हूं मैं कह रहा हूं यह सबूत नहीं है क्या?

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोकसभा चुनाव परिणाम की समीक्षा के लिए मंडलवार जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर रहे है। पूर्वांचल और अवध के मंडलों की समीक्षा के बाद अब पश्चिम के मंडलों की समीक्षा शुरू हो चुकी है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को मेरठ मंडल के जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की। जहां मुख्यमंत्री ने बुधवार विधायकों को क्षेत्र की जनता से बराबर संवाद बनाए रखने और उनकी समस्याओं के प्रति संवेदनशील बनने की भी सलाह देने के साथ ही अधिकारियों के खिलाफ ठोस सबूत लाने की बात कही। विधायकों द्वारा अधिकारियों के न सुनने की शिकायत पर मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि यदि कोई अधिकारी नहीं सुन रहा है तो उसके खिलाफ ठोस सबूत के साथ शिकायत करें, तभी उस अधिकारी के खिलाफ तत्काल कार्रवाई होगी। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की समीक्षा लोकसभा चुनाव में यूपी में बीजेपी के खराब प्रदर्शन की हो रही है। सीएम लखनऊ स्थित अपने सरकारी आवास पर बीजेपी के विधायकों और सांसदों को बुला रहे हैं बीजेपी के सहयोगी दलों के विधायकों और सांसदों को भी बुलाया जा रहा है। योगी आदित्यनाथ एक कॉमन सवाल सबसे पूछते हैं कि बीजेपी को वोट कम क्यों मिले? सूत्रों की माने तो इस हार को लेकर ज्यादातर विधायकों ने सीएम योगी से कहा कि विपक्ष का पड़ा का फैलाया हुआ झूठ पूरी तरह से लोगों के दिमाग

में भर गया था और इसके साथ ही अधिकारियों हमारे कार्यकर्ताओं के अंदर नाराजगी थी कि हम उनका कोई काम नहीं कर पा रहे हैं सही काम के लिए भी अधिकारी करने को तैयार नहीं होते थे जिससे कि इस लोकसभा चुनाव में अपना ही कार्यकर्ता संवेदनशील नहीं रहा।

विधायकों द्वारा अधिकारियों के न सुनने की शिकायत पर मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि यदि कोई अधिकारी नहीं सुन रहा है तो उसके खिलाफ ठोस सबूत के साथ शिकायत करें, तभी उस अधिकारी के खिलाफ तत्काल कार्रवाई होगी।मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक के जनप्रतिनिधियों से अधिकारियों के खिलाफ ठोस सबूत लाने की बात कही लेकिन उनके इस निर्देश पर गाजियाबाद के लोनी से विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने कहा कि अधिकारी मनमानी करते हैं जहा तकसबूत की बात है तो... सबूत क्या होता है मैं विधायक हूं मैं कह रहा हूं यह सबूत नहीं है क्या, विधायक का प्रोटोकॉल चीफ सेक्रेटरी से ऊपर होता है।

अकबरनगर के बाद चौक फूल मंडी भी खत्म, हुआ जबरदस्त बुलडोजर एक्शन

लखनऊ। राजधानी में प्रशासन का बुलडोजर एक्शन जारी है। जहाँ एक तरफ अकबरनगर में अवैध अतिक्रमण को लेकर बड़ी कार्रवाई को लखनऊ विकास प्राधिकरण ने अंजाम दिया था, वहीं अब ऐसी ही कार्रवाई मशहूर चौक फूल मंडी में हुई है। गुरुवार को हुसैनाबाद ट्रस्ट की जमीन पर चौक स्थित कंचन मार्केट के सामने लगने वाली फूल मंडी पर बुलडोजर चलाया गया है। यहां मौजूद छोटे–बड़े कई निर्माण को प्रशासन ने जमींदोज कर

दिया है। कई बरसों से यहां जमीन पर थोक में फूल बेचने वाले अपना कारोबार चलाते थे। गुरुवार को फूल मंडी हटाने के दौरान नगर निगम टीम के साथ हुसैनाबाद ट्रस्ट के लोग भी मौके पर मौजूद रहे। भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में बुलडोजर से वहां बने निर्माणों को ध्वस्त किया गया। ये पूरी कार्रवाई एसडीएम और एसीपी चौक की मौजूदगी में हुई। बताते चलें कि 29 सितम्बर 2019 को विभूति खंड, गोमती नगर स्थित किसान बाजार में चौक फूलमंडी को स्थांनांतरित किया गया था। जिसके बाद फूल व्यापारी कल्याण समिति ने स्वयं फूल मंडी हटाने का समय मांगा था। बताया जा रहा है कि तय समय में मंडी न हटाए जाने के बाद ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई है।

सीसामऊ से नसीम सोलंकी होंगी सपा की प्रत्याशी

उपचुनाव: समाजवादी पार्टी ने खोला पहला पत्ता

लखनऊ, (यूएनएस)। उपचुनाव को लेकर सपा ने पहला पत्ता खोला। सीसामऊ से नसीम सोलंकी का टिकट फाइनल किया। कानपुर की सीसामऊ विधानसभा सीट जिसपर लंबे समय से सपा का कब्जा कायम है। सपा विधायक इरफान सोलंकी को सुनाई गई सजा के कारण उनकी विधायकी रद्द हो जाने के कारण यह सीट रिक्त हुई है। सपा इस सीट पर उपचुनाव के समीकरण तैयार कर चुकी है। बीजेपी इस सीट को उपचुनाव में हथियाना चाहती है वहीं विधायक इरफान की सजा पर स्टे की कवायत भी जारी है। सपा के राष्ट्रीय नेतृत्व की ओर से कानपुर में संदेश पहुंचा दिया गया है की इस सीट से सपा को कोई और नेता या चेहरा चुनाव नहीं लड़ेगा बल्कि जेल में बंद विधायक इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम दावेदार है और वही प्रत्याशी भी। अटकलों पर कानपुर के सपा जिलाध्यक्ष गजल महमूद ने विराम लगा दिया है।सीसामऊ सीट पर इरफान सोलंकी के जेल जाने के बाद सपा के कई दिग्गज इस सीट से अपना भाग्य आजमाना चाहते थे क्योंकि ये सीट हर हाल में चुनाव के दौरान सपा एक पाले में ही जाने के आसार दिखते हैं लेकिन कानपुर से सपा के जिलाध्यक्ष ने साफ कर दिया कि स्वयं अखिलेश यादव ने नसीम सोलंकी का नाम लिया और कहा है की जाकर तैयारी में लगो ,जिसके बाद अन्य नेताओं की दावेदारी और अटकलें थम गई।कांग्रेस भी इस सीट पर अपना अभाग्य आजमाना चाहती हैं क्योंकि लोकसभा में हुए गठबंधन के बाद उम्मीदें जीत की ज्यादा जग गई हैं।

तगड़ा झटका लगा तो ओबीसी की आई सुधि

बीजेपी का रुठों को मनाने का प्लान,29 को हाई लेबल मीटिंग

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में पिछड़ा वर्ग को साधने के लिए बीजेपी ने कोशिशें तेज कर दी हैं। ओबीसी नेताओं की बड़ी बैठक होने जा रही है। बैठक में ओबीसी नेताओं के साथ चर्चा होगी। यूपी सरकार में मंत्री और ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष नरेंद्र कश्यप ने कहा कि ओबीसी समाज को एक साथ लाना और नाराजगी की वजह जानी जाएगी।कश्यप ने भी कहा कि संगठन सरकार से बड़ा है। संगठन है तो ही सरकार है।बीजेपी 29 जुलाई को ओबीसी कार्य समिति की बैठक करने वाली है जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और बृजेश पाठक समेत बीजेपी के बड़े नेता शामिल होंग। बैठक का एजेंडा है कि कैसे ओबीसी वोट बैंक को बनाए रखा जाए।अगर नाराजगी की वजह से ओबीसी कहीं और शिफ्ट हुए हैं तो उन्हें कैसे वापस लाया जाए। बीजेपी नेताओं के अति आत्मविश्वास की वजह से यूपी में नुकसान झेलना पड़ा है।उधर समाजवादी पार्टी के नेता उदयवीर सिंह ने ओबीसी समाज की बैठक को लेकर कहा, ओबीसी अब समझ चुका है कि पीडीए में ही भविष्य है, बीजेपी सिर्फ आपस में लड़ाने की राजनीति करती है।यह लोग आपस में ही लड़े जा रहे हैं।अधिकारी इतने हावी हैं कि संगठन की नहीं चल रही है। विधानमंडल की बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष तय करेंगे कि कौन नेता प्रतिपक्ष होगा। उत्तर प्रदेश की राजनीति में हर दल पिछड़ा वर्ग को साधने की कोशिश करता है। आम चुनाव के नतीजे आए तो कहा गया कि नाराज पिछड़ा वर्ग ने इस बार बीजेपी से दूरी बना ली है।लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने यूपी में 33 सीटें जीतीं जबकि 2019 के चुनावों में 62 सीटों पर जीत हासिल की थी। 2014 में बीजेपी ने यूपी में 71 सीटों पर जीत हासिल की थी। कमजोर प्रदर्शन में पिछड़ा वर्ग की नाराजगी एक महत्वपूर्ण कारण रहा है। यूपी में पिछड़ा वर्ग की आबादी जनसंख्या का लगभग 50 फीसदी है, जो चुनावी दृष्टि से महत्वपूर्ण वोट बैंक है। लोकसभा चुनाव में इस बार सबसे ज्यादा 37 सीटें सपा ने जीती हैं। कांग्रेस ने 6 सीटों पर जीत हासिल की है। बीजेपी के सहयोगी दल आरएलडी ने 2, अपना दल एस ने एक सीट पर जीत हासिल की है।बसपा खाता नहीं खोल सकी है। सपा बसपा द्वारा ओबीसी समुदायों को लुभाने की कोशिशें बीजेपी के लिए चुनौती बन रही है। कई ओबीसी नेताओं ने पार्टी से इस्तीफा दिया और और सपा समेत अन्य दलों में शामिल हो गए।ओबीसी समुदाय का मानना है कि बीजेपी ने उनके लिए पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं दिया है और आरक्षण के मुद्दों पर भी पार्टी की नीति में सुधार की आवश्यकता है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा सुझाया गया पीडीए पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक फॉर्मूला आम चुनावों में बीजेपी के खिलाफ एक महत्वपूर्ण रणनीति के रूप में देखा गया। फॉर्मूले के तहत समाजवादी पार्टी ने पिछड़े वर्गों, दलितों और अल्पसंख्यकों को एकजुट करने का लक्ष्य रखा है।इस रणनीति का उद्देश्य इनके समर्थन से एनडीए को चुनौती देना है।

पेट्रोल पम्प से ३ लाख की नकदी ले उड़े बेखौफ चोर, जांच में जुटी पुलिस

बहराइच, (यूएनएस)। फखरपुर थाना क्षेत्र के अखनापुर गांव में स्थित पेट्रोल पम्प परिसर में बने कमरे की आलमारी में रखी 3 लाख से अधिक की नकदी को बुधवार की रात को चोरों ने चुरा लिया। सुबह जानकारी होने पर सीओ ने पुलिस टीम के साथ मौके पर निरीक्षण किया है। पेट्रोल पंप के प्रोपराइटर मोहम्मद लुकमान ने बताया कि फखरपुर थाना अंतर्गत अखनापुर में उनका पेट्रोल पंप है। बुधवार की देर रात अज्ञात चोर खिड़की के रास्ते उस कमरे में घुसे जिसमें कैश रखा था। उन्होंने वहां रखी चाबी से अलमारी के लाकर को खोल कर 3 लाख से अधिक की नकदी को पार कर दिया। चोरी की घटना के सीसीटीवी फुटेज भी मौजूद है। पेट्रोल पंप पर तीन नाजिल मैन व एक चौकीदार भी रात में थे, लेकिन वह सो रहे थे। इसी बीच मौका पाकर चोरों ने इस घटना को अंजाम दिया। घटना की जांच करने पँहुचे सीओ रूपेंद्र कुमार गौड़ ने बताया एसओजी सर्विलांस की टीम ने भी जांच की है। चोरों के फोटो भी सीसीटीवी में आए है। जल्द चोरी का खुलासा हो जाएगा।

कावड़ यात्रा कि इसकी सुनवाई संवैधानिक पीठ द्वारा की जानी चाहिए

लखनऊ। सनातन ब्रह्म फाउंडेशन, सनातन महासभा भारत तथा भारत रक्षा दल ट्रस्ट आदि विभिन्न संस्थाओं द्वारा गुरूवार को प्रेस क्लब में कांवड़ यात्री न्यायार्थ सर्वोच्च न्यायालय में पक्ष रखने हेतु सभा का आयोजन किया गया। सभा मे सनातनधर्मियों को एकजुट करने व सरकार पर दबाव बनाने के लिए कई संस्थाओं ने आह्वानकिया। खचाखच भरे हाल में कुमार अशोक पाण्डेय ने विषय रखते हुए कहा कि हमारी मांग है कि इसकी सुनवाई संवैधानिक पीठ द्वारा की जानी चाहिए तथा सर्वोच्च न्यायालय में योग्यतम वकीलों के द्वारा सरकार को पक्ष रखना चाहिए। भाजपा नेता मनीष शुक्ल ने बताया कि सरकार ने इस संबंध में कोई नया कानून नहीं बनाया है अपितु खाद्य सुरक्षा कानून 2006 तथा स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट 2014 को ठीक ढंग से लागू किया गया है, ये दोनों कानून भाजपा सरकार ने नहीं बनाये हैं। श्री देवेन्द्र शुक्ल ने कहा कि ईश्वर के बाद न्याय की आशा में लोग सर्वोच्च न्यायालय जाते हैं, अतः हमें पूर्ण विश्वास है कि छद्मवेष धारण करके सामान बेचने वाले लोगों पर कानून अपना शिकंजा अवश्य कसेगा। जिस प्रकार नकली सरकारी सेवक बनकर वसूली करने वालों से कानून सख्ती से निपटता है उसी प्रकार इन बहरूपियों के विरुद्ध भी कार्रवाई अवश्य की जाएगी! श्री सुधाकर त्रिपाठी ने मांग करते हुए कहा कि कांवड़ यात्रा की शुचिता और पवित्रता बनाए रखने हेतु सरकार को एकजुट होकर सरकार पर दबाव बनाने का आह्वान किया साथ ही चेतावनी देते हुए कहा कि हमारी परम्पराओं एवं संस्कृति से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। इस अवसर पर पननु कश्मीर के अध्यक्ष रवि कचरू, एडवोकेट अनुभव शुक्ल, जे. पी. पाण्डेय, भट्ट ब्राह्मण सभा

हरसंभव प्रयास करे। श्रीमती आहुति बाजपेयी ने इस हेतु लोगों को जागरूक करने पर जोर दिया और कहा कि यह जिम्मेदारी हमें स्वयं लेनी होगी। श्री निवास राय ने क्षोभ व्यक्त करते हुए कहा कि हमारी संस्कृति को नष्ट–भ्रष्ट करने की कोशिश की जा रही है, हम इसे कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। सभा का संचालन करते हुए डॉ प्रवीण ने सभी सनातनधर्मियों के राजेश शर्मा, डॉ भानु पांडेय,,वेद प्रकाश शर्मा, विजय मिश्र, विजय अवस्थी, सुधांशु शुक्ल, रामरूप यादव, श्री कौशिक बनर्जी, नीलिमा त्रिपाठी, रेनू शर्मा, पूनम शर्मा, मीनू तिवारी, सुरेन्द्र शर्मा, रामू सान्याल, असीम पाण्डेय, गिरिजा शंकर त्रिपाठी, शैलेन्द्र श्रीवास्तव, लखन द्विवेदी, मधुबाला आदि बहुत से लोग उपस्थित हुए।

भगवान बुद्ध से जुड़े स्थलों का हो रहा विकास

168.39 करोड़ रूपये से शुरू हुए विकास कार्य

देश–दुनिया से आने वाले बौद्ध अनुयायी सुखद अनुभूति लेकर लौंटे : जयवीर

लखनऊ। उत्तर प्रदेश पौराणिक काल से ही आस्था का केन्द्र रहा है। यहां की धरती पर पग–पग पर महापुरूषों, ऋषियों, मुनियों तथा समाज को लोक कल्याण का संदेश देने वाले महामानवों की जन्म स्थली एवं कर्मस्थली पायी जाती है। भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़े 06 प्रमुख स्थल यूपी में मौजूद हैं, जो देश–विदेश के बौद्ध अनुयायियों के लिए आकर्षण के केन्द्र हैं। श्रद्धालुओं की इन स्थलों पर भारी भीड़ देखते हुए राज्य सरकार ने भगवान बुद्ध से जुड़े स्थलों का 168.39 करोड़ रूपये की लागत से बुनियादी सुविधाओं का विकास कर रही है। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि 168.39 करोड़ रूपये से पर्यटन स्थल पर पर्यटक सुविधाओं के विकास की प्रक्रिया शुरू हो गयी है। कुशीनगर, श्रावस्ती, कौशाम्बी, संकिसा, कपिलवस्तु व वाराणसी के सारनाथ समेत अन्य बौद्ध स्थलों पर अवस्थापना सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। प्रमुख बौद्ध स्थलों पर आने वाले श्रद्धालु एक सुखद अनुभूति का एहसास कर सके, इस दृष्टि से इन स्थलों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप विकसित किया जा रहा है। कुशीनगर में लगभग 8.06 करोड़ से टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर, कुशीनगर रामाभार स्तूप के सन्निकट बुद्ध घाट पर 23.81 करोड़ रुपये से पर्यटन सुविधाओं का विकास, सौंदर्यीकरण कार्य कराया जाएगा। मुख्य प्रवेश मार्गों पर 4.25 करोड़ से गेट कांप्लेक्स का निर्माण, कुशीनगर स्थित बौद्ध विहारों पर लगभग 3.57 करोड़ से पर्यटन सुविधाएं विकसित की जाएंगी। श्रावस्ती स्थित बौद्ध विहारों पर लगभग 6.78 करोड़ से पर्यटन सुविधाओं का विकास किया जाएगा। कौशांबी में बौद्ध थीम पार्क का निर्माण 22.94 करोड़ की लागत से किया जाएगा। लगभग 11.25 करोड़ रुपये से भगवान बुद्ध की 51 फीट ऊंची ध्यान मुद्रा में कांस्य प्रतिमा स्थापित की जाएगी। ग्राम कोसम इनाम में गेट कांप्लेक्स का निर्माण लगभग 23.95 करोड़ रुपये की लागत से किया जाएगा। सिद्धार्थनगर स्थित कपिलवस्तु का समेकित पर्यटन विकास लगभग 9.77 करोड़ से किया जाएगा। यहां बौद्ध विहारों पर 4.63 करोड़ से पर्यटन सुविधाओं का सृजन किया जाएगा। कपिलवस्तु में विपश्यना केंद्र का निर्माण 24.37 करोड़ की लागत से किया जा रहा है। भगवान बुद्ध की प्रथम उपदेश स्थली धमेक स्तूप पर 9.63 करोड़ रुपये से ध्वनि एवं प्रकाश कार्यक्रम, मूलगंध कुटी विहार पर लगभग 3.95 करोड़ से फसाड लाइट का कार्य किया जाएगा। फर्रूखाबाद जिले में लगभग 3.18 करोड़ से बौद्ध परिपथ क्षेत्र में साइनेज स्थापना का कार्य किया जाएगा। संकिसा में पर्यटकों की सुविधा के लिए लगभग 1.50 करोड़ से साइनेज का निर्माण किया जाएगा। इसी तरह श्रावस्ती में पर्यटकों की सुविधा के लिए लगभग 3.61 करोड़ से साइनेज लगाए जाएंगे। वाराणसी में सारनाथ में पर्यटकों की सुविधाओं के लिए लगभग 3.17 करोड़ से साइनेज लगेंगे। यह प्रमुख योजनाएं है जिससे बौद्ध सर्किट के विकास की तैयारी है। वाराणसी जिले में स्थित सारनाथ जहां 2,500 साल पहले भगवान बुद्ध ने अपने पहले पांच शिष्यों को 'चार आर्य सत्य' का प्रथम धर्म उपदेश दिया था, जो 21वीं सदी में कई समस्याओं के समाधान के लिए प्रासंगिक है। कुशीनगर वह स्थान है, जहां गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। इन छह स्थलों के अलावा जिला महराजगंज में स्थित रामग्राम कोलिय साम्राज्य का प्रमुख नगर था। मान्यता है कि रामग्राम स्तूप में भगवान् बुद्ध के अवशेष मौजूद हैं।

खनिज परिवहन करने वाले वाहनों के साथ ई–अभिवहन प्रपत्र की नवीन व्यवस्था होगी लागू

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में खनिज परिवहन करने वाले वाहनों के साथ ई– एम एम– 11 की वर्तमान में लागू व्यवस्था को अवक्रमित करते हुए नई व्यवस्था लागू करने के निर्देश उत्तर प्रदेश शासन द्वारा समस्त जिला अधिकारियों व निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग उत्तर प्रदेश को दिए गए हैं। यह नवीन विकेंद्रीकृत व्यवस्था लागू करने हेतु प्रमुख सचिव भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा शासनादेश जारी कर दिया गया है।उप खनिजों के खनन पट्टा तथा खनिज खनन अनुज्ञा से संबंधित कार्य के समयबद्ध एवं सुचार संचालन के हित में ई एमएम– 11 जनरेशन हेतु विभागीय पोर्टल नचउपदमे.नचेकब.हवअ.पद पर फीडिंग की व्यवस्था विकेंद्रीकृत करते हुए संबंधित जिलाधिकारी के अनुमोदन से जनपदीय खान अधिकारी के लागिन पर उपलब्ध वेब पेज के माध्यम से कराया जाएगा।जारी शासनादेश में जनपद स्तर पर की जाने वाली कार्रवाही, परिहारधारकों द्वारा की जाने वाली कार्रवाही तथा भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय स्तर पर की जाने वाली कार्रवाही के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। यह व्यवस्था 01 अगस्त 2024 से प्रवृत लागू होगी। शासनादेश में कहा गया है कि संबंधित जनपद में तैनात ज्येष्ठ खान अधिकारी ,खान अधिकारी ,खान निरीक्षक द्वारा निर्धारित प्रारूप पर परिहारधारकों का विवरण तैयार किया जाएगा, और तैयार सूचना को स्वहस्ताक्षरोपरान्त जनपद के मुख्य कोषाधिकारी अथवा उनके द्वारा नामित प्रभारी अधिकारी व जिलाधिकारी द्वारा नामित प्रभारी अधिकारी खनन से सत्यापित कराकर जिलाधिकारी से प्रतिहस्ताक्षरित कराया जाएगा।डाटाबेस तैयार करने हेतु परिहार धारकों को अपना आधार नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी ,जीएसटी नंबर, पैन नंबर आदि विवरण निर्धारित प्रारूप पर स्वप्रमाणित कर जिला अधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत किया जाएगा, जिसके आधार पर जिले के ज्येष्ठ खान अधिकारी,खान अधिकारी खान निरीक्षक द्वारा निर्धारित प्रारूप पर विवरण तैयार किया जाएगा। खनन निदेशालय स्तर पर पोर्टल के अनुश्रवण हेतु ई–एमएम 11प्रकोष्ठ होगा । प्रकोष्ठ द्वारा डाटा व अन्य सूचनाओं का परीक्षण किया जाएगा तथा तकनीकी समस्याओं का निराकरण कराया जाएगा।प्रमुख सचिव भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जिलाधिकारी को निर्देश दिए गए हैं कि प्रदेश में खनन परिहार धारकों द्वारा खनिज परिवहन करने वाले वाहनों के साथ नई व्यवस्था के अनुसार ई–एमएम–11 जेनरेशन हेतु विभागीय पोर्टल नचउपदमे. नचेपकब.हवअ.पद पर फीडिंग आदि की प्रक्रिया अपनाई जाने के संबंध में दिए गए निर्देशों के अनुसार कार्यवाही की जाए।

सम्पादकीय

दीर्घकालिक संभावनाओं के लिए स्पष्ट दूरदर्शी दृष्टिकोण का सुझाव

आर्थिक सर्वेक्षण 2023–24 भारत की विकास कहानी की एक सुखद तस्वीर पेश करता है और अल्पकालिक संभावनाओं को अच्छा मानता है, लेकिन चिंता के कई क्षेत्रों को चिह्नित करने में विफल नहीं होता है। बेहतर दीर्घकालिक संभावनाओं के लिए यह स्पष्ट दूरदर्शी दृष्टिकोण की आवश्यकता पर बल देता है। इसने कृषि में व्यापक सुधार की तत्काल जरूरतों को रेखांकित किया–श्भारत के विकास पथ में अपनी केंद्रीयता के बावजूद, कृषि क्षेत्र को संरचनात्मक मुद्दों का सामना करना पड़ रहा है, जिसका भारत के आर्थिक विकास पर प्रभाव पड़ता है,श इसने क्षेत्र के सामने कई प्रमुख चुनौतियों की पहचान करते हुए कहा, जिसमें खाद्य मूल्य मुद्रास्फीति का प्रबंधन करते हुए विकास को बनाये रखने की आवश्यकता, फसलों के मूल्य निर्धारण तंत्र में सुधार और भूमि विखंडन को संबोधित करना शामिल है। इसमें कहा गया है कि नीति निर्माताओं को किसानों को उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने और खाद्य कीमतों को स्वीकार्य सीमा के भीतर रखने के बीच एक नाजुक संतुलन बनाना चाहिए। इस दोहरे उद्देश्य के लिए सावधानीपूर्वक नीतिगत हस्तक्षेप की आवश्यकता है।

हालांकि आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया है कि भारत के श्रम बाजार संकेतकों में सुधार हुआ है, लेकिन यह चेतावनी देता है कि आर्थिक गतिविधि के कई क्षेत्रों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता की जड़ें जम रही हैं और इसलिए सामूहिक कल्याण की दिशा में तकनीकी विकल्पों को आगे बढ़ाना महत्वपूर्ण होगा। हालांकि, यह सरकार पर नहीं बल्कि नियोक्ताओं पर जिम्मेदारी डालता है कि वे प्रौद्योगिकी और श्रम के बीच संतुलन बनाने के लिए जिम्मेदार हैं। इसमें कहा गया है कि कई विनियामक नियंत्रण, जैसे कि भूमि उपयोग, भवन संहिता, महिलाओं के रोजगार के लिए खुले क्षेत्रों और घंटों को प्रतिबंधित करना, रोजगार सृजन को रोकते हैं। सर्वेक्षण ने रुपये की अस्थिरता को नोट किया, लेकिन कहा कि यह सबसे कम अस्थिर मुद्राओं में से एक है, जो सांत्वना के अलावा और कुछ नहीं है। वित्त वर्ष 24 में, अमेरिकी डॉलर ने लगभग हर प्रमुख समकक्ष के मुकाबले बढ़त हासिल की। रुपया भी मूल्यह्रास दबाव में आया। इसके अलावा, दस्तावेज में जोर दिया गया है कि वित्त वर्ष 24 में इसने पिछले वर्षों की तुलना में सबसे कम अस्थिरता प्रदर्शित की। यह विश्व अर्थव्यवस्था पर चीन के वैश्विक प्रभाव का भी उल्लेख करता है, और कहता है कि दुनिया चीन को पूरी तरह से अनदेखा नहीं कर सकती, भले ही वह चीन के साथ–साथ एक और देश की ओर क्यों न बढ़ रही हो। अपने निष्कर्ष के समर्थन में सर्वेक्षण कहता है कि मेक्सिको, वियतनाम, ताइवान और कोरिया जैसे देश, जो चीन से अमेरिका के व्यापार मोड़ के प्रत्यक्ष लाभार्थी थे। जबकि इन देशों ने अमेरिका को निर्यात में अपना हिस्सा बढ़ाया, उन्होंने चीनी एफडीआई में भी वृद्धि दिखाई। दिए गए उदाहरण में भारत के श्विकसित भारतश की ओर बढ़ने के संबंध में कई छिपे हुए अर्थ हैं। सर्वेक्षण कहता है कि यह 1980 और 2015 के बीच चीन के आर्थिक उछाल से अलग होगा – और यह एक आसान रास्ता नहीं होगा। यह कारण गिनाता है कि क्यों? यह कहता है कि शीत युद्ध के अंत में भू–राजनीति काफी हद तक शांत थी, और पश्चिमी शक्तियों ने चीन का स्वागत किया और यहां तक कि इसके उदय और विश्व अर्थव्यवस्था में इसके एकीकरण को प्रोत्साहित किया। वैश्वीकरण अपने लंबे विस्तार के शिखर पर था, और जलवायु परिवर्तन और वैश्विक चेतावनी पर चिंताएं तब इतनी व्यापक या गंभीर नहीं थीं जितनी कि वे अब हैं। यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आगमन की ओर इशारा करता है, जो सभी कौशल स्तरों – निम्न, अर्ध और उच्च – के श्रमिकों पर इसके प्रभाव के बारे में अनिश्चितता की एक बड़ी परत डालता है। ये आने वाले वर्षों और दशकों में भारत के लिए निरंतर उच्च विकास दर के लिए अवरोध और बाधाएं पैदा करेंगे। इन पर काबू पाने के लिए संघ और राज्य सरकारों और निजी क्षेत्र के बीच एक शानदार गठबंधन की आवश्यकता है। देश के कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए, यह कहता है कि हम कल्याण के लिए एक सुधारित दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ रहे हैं, जो सशक्तिकरण, संतृप्ति दृष्टिकोण, आवश्यकताओं तक सार्वभौमिक पहुंच, दक्षता, लागत–प्रभावशीलता और निजीक्षेत्र और नागरिक समाज की भागीदारी बढ़ाने पर केंद्रित है। हालांकि, जहां तक उनके प्रदर्शन और इरादों का सवाल है, दावे बहस और प्रतिवाद योग्य हैं। सर्वेक्षण में कहा गया है कि भारत का बाहरी क्षेत्र मजबूत बना हुआ है, चल रही भू–राजनीतिक प्रतिकूलताओं के साथ–साथ चिपचिपी मुद्रास्फीति के बीच। भारत में मुद्रास्फीति को दोहरे मानक से निपटाया गया है। एक तरफ यह स्वीकार करता है कि पिछले दो वर्षों में प्रतिकूल मौसम की स्थिति से खाद्य कीमतें प्रभावित हुई हैं, और इन घटनाक्रमों का शुद्ध प्रभाव वित्त वर्ष 23 और वित्त वर्ष 24 में मुद्रास्फीति का दबाव बढ़ा है। हालांकि, वित्त वर्ष 25 या उसके बाद की मुद्रास्फीति के संबंध ा में, यह सामान्य जलवायु स्थितियों और सामान्य आंतरिक और बाहरी कारकों पर अनुमान लगाता है। हालांकि, सर्वेक्षण यह भी स्वीकार करता है कि मध्यम से दीर्घकालिक मुद्रास्फीति का दृष्टिकोण इसके परे के कारकों पर निर्भर करेगा जिनमें मूल्य निगरानी तंत्र और बाजार खुफिया को मजबूत करने के साथ–साथ दालों और खाद्य तेलों जैसे आवश्यक खाद्य पदार्थों के घरेलू उत्पादन को बढ़ाने के लिए केंद्रित प्रयासों की आवश्यकता होगी, परन्तु भारत उनके लिए काफी हद तक आयात पर निर्भर है। इसमें कहा गया है कि दीर्घकालिक मूल्य स्थिरता प्राप्त करने के लिए एक स्पष्ट दूरदर्शी दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। इसलिए मौसमी मूल्य वृद्धि को प्रबंधित करने के लिए फलों और सब्जियों के लिए आधुनिक भंडारण और प्रसंस्करण सुविधाओं के विकास में प्रगति का आकलन करना महत्वपूर्ण है। भारत की विकास कहानी की प्रशंसा करते हुए,सर्वेक्षण में कहा गया है कि महामारी के बाद भारत की अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ है और इसका विस्तार हुआ है। वित्त वर्ष 2024 में वास्तविक जीडीपी वित्त वर्ष 20 के स्तर से 20प्रतिशत अधिक थी, इसमें कहा गया है। इसने वित्त वर्ष 2025 में भी मजबूत वृद्धि जारी रहने की संभावना अच्छी बताई है, लेकिन वह भू–राजनीतिक, वित्तीय बाजार और जलवायु जोखिमों के अधीन है। इसमें आगे चेतावनी दी गई है कि 2024 में भू–राजनीतिक संघर्षों के बढ़ने से आपूर्ति में अव्यवस्था, आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि, मुद्रास्फीति के दबाव में वृद्धि और पूंजी प्रवाह के लिए संभावित नतीजों के साथ मौद्रिक नीति में ढील को रोकना पड़ सकता है। यह आरबीआई की मौद्रिक नीति के रुख को भी प्रभावित कर सकता है। सर्वेक्षण में भू–राजनीतिक रेखाओं के साथ बढ़ते विखंडन और संरक्षणवाद पर नये सिरे से जोर देने के बारे में भी चेतावनी दी गई है, जो भारत के बाहरी क्षेत्र को प्रभावित करने वाले व्यापारिक विकास को विकृत कर सकता है। वैश्विक वित्तीय बाजारों ने नयी ऊंचाइयों को छुआ है तथा निवेशक वैश्विक आर्थिक विस्तार पर दांव लगा रहे हैं। हालांकि, ऊंचे वित्तीय बाजार मूल्यांकन में किसी भी सुधार का घरेलू वित्त विकास की संभावना पर असर पड़ सकता है।

गला घोंटने वाले का ही जब गला घुटने लगे...

पिछले लगभग एक दशक से देश का नेतृत्व कर रहे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपने व्यक्तित्व में समाये कई–कई विरोधाभासों एवं विसंगतियों का अनेक अवसरों पर परिचय दिया है। मसलन, वे खुद को गरीब व ओबीसी का बतलाते रहे हैं परन्तु उनकी जीवन शैली ऐसी है जो अच्छे से अच्छे रईसों के ठाठ–बाट को भी लजा दे। वे संविधान की हिफाजत की बात करते हैं लेकिन राजतंत्र के प्रतीक सेंगोल को सीने से लगाये रखते हैं। भारत को श्लोकतंत्र की जननीश कहेंगे परन्तु उसे कुचलने का सबसे अधिक काम उन्हीं के शासन काल में होता है। सकारात्मकता की बात करेंगे लेकिन उनके भाषणों में हर वक्त बीते समय को लेकर और कुछ लोगों–संगठनों के प्रति घृणा की अभिव्यक्ति होती है। उनके कार्यों व नीतियों में भी इसी विरोधाभास का परिचय मिलता है। एक ओर वे भारत को दुनिया की एक बड़ी इकानॉमी बताएंगे वहीं वे 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देने की योजना को चालू रखे हुए हैं। भारत को विश्वगुरु बतलाते हैं पर बातें ऐसी करते हैं कि अज्ञानता भी यह कहकर लज्जित हो जाये, कि श्बस कीजिये मोदी जी! मेरी भी एक सीमा हैश हरि अनंता, हरि कथा अनंता की भांति पीएम के अनेक किस्से हैं। बहुत पुराने नहीं हैं। ताजातरीन दृष्टांत इन सबसे ऊपर है। सोमवार को जब संसद का बजट सत्र प्रारम्भ हुआ तो उनकी नयी स्थापित की गयी परम्परा के अनुरूप श्री मोदी ने प्रेस के समक्ष अपने उद्बोधन में इस बात का दुखड़ा रोया कि श्ढाई घंटे तक देश के प्रधानमंत्री का गला विपक्ष ने घोंटा थाश उनका इशारा नयी सरकार के पहले सत्र की ओर था जिसमें संसद के दोनों सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा हुई थी। दरअसल इस सत्र में मोदीजी की भरपूर फजीहत हुई थी क्योंकि उनका 370–400 का नारा बुरी तरह से पिट गया था और जिस विपक्ष से मुक्तभारत की वे बात करते थे, वह पहले के मुकाबिल बहुत बड़े स्वरूप में उनके सामने बैठा हुआ था। जिस नेहरू खानदान को वे दिन–रात कोसते हैं और जिस राहुल गांधी को वे बहुत खराब शब्दावली से नवाजा करते हैं, वह लोकसभा में प्रतिपक्ष का नेता बनकर उन पर सवाल पर सवाल दाग रहे थे। राहुल के साथ अनेक और महत्वपूर्ण विपक्षी नेता भी उनके समक्ष बैठते हैं। यह स्थिति सोमवार से जारी बजट सत्र में हैय और यह सरकार जब तक चलेगी तब तक रहेगी।

वैसे अगर इस बात पर कोई शायद ही यकीन करे कि मोदी का गला कोई घोंट सकता है। एक क्षण को मान लेते हैं कि उनका गला वाकई घोंटा गया है तो यह किसी भी देश के लिये बहुत चिंताजनक बात है। स्वयं मोदी जी के सोचने की बात है कि आखिर यह देश ऐसा कैसे बन गया जहां पीएम का भी गला घोंटा जा सकता है। अब तक तो कमजोर से कमजोर प्रधानमंत्री ने भी यह शिकायत नहीं की थी। वैसे तो किसी भी राष्ट्राध्यक्ष को यह कहने का अधिकार ही नहीं है कि वह अपना गला घोंटे जाने की शिकायत करे। उसका काम लोगों के घुटते गलों को आजाद कराना है। गरीबी से जिनके गले घुटे हैं, किसी भी तरह के भेदभाव से पीड़ित जिस अवाम का गला घोंटा गया है, अशिक्षा के कारण जो बोल नहीं पाते, जिनके अधिकार छीन लिये गये हैं– उन सब की आवाज ही राष्ट्रप्रमुख होता है। चूंकि ऐसे दबे–कुचलों को आवाज देने का काम संविधान का है, प्रधानमंत्री को उसकी रक्षा करना होता है। एक ऐसी व्यवस्था बनाना ही प्रधानमंत्री का उत्तरदायित्व है कि जिसमें किसी का गला न घुटे। यदि प्रधानमंत्री मोदी यह सचमुच जानना चाहते हैं कि उनका गला कैसे घोंटा गया है या वे ऐसा क्यों महसूस करते हैं तो उन्हें सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश के उस वाक्य को याद करना होगा जिसमें उन्हेंने कहा था कि श्आलोचना प्रेशर कुकर की सीटी की तरह है। वह अगर न बजती रहे तो कुकर का फटना तय है।श लोकतंत्र में सरकार की आलोचना इतनी जरूरी है कि यदि न होती रहे तो न केवल जनता और विपक्ष बल्कि स्वयं सत्ताधीशों का कुकर की तरह फट पड़ना लाजिमी है। आलोचना और उसका तर्कसंगत व तथ्यात्मक जवाब देने से अंदर की भाप निकलती रहती है जिससे लोकतंत्र सुरक्षित रहता है। इस सिद्धांत के विपरीत मोदीजी ने आलोचना के सारे रास्ते बन्द कर दिये हैं। सदन के भीतर वे विपक्ष का जवाब नहीं देते और बाहर वे खुली पत्रकार वार्ताएं या बातचीत नहीं करते जैसी कि सारे राष्ट्राध्यक्ष करते हैं। विपक्षी दलों के साथ किसी भी कार्यक्रम व नीतियों पर संवाद नहीं रखते। यहां तक कि खुद अपनी ही पार्टी के भीतर वे किसी मसले पर राय–मशविरा नहीं करते। ले–देकर केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह हैं जिनके साथ मिलकर फैसले होते हैं। नोटबन्दी होती है तो वित्त मंत्री को पता नहीं होता, नयी ट्रेनों को मोदी जब झंडी दिखाते हैं तो रेल मंत्री आसपास भी नहीं फटक सकते, हाईवे या फ्लाईओवर का उद्घाटन होता है तो सड़क परिवहन मंत्री देश के किसी दूसरे कोने में विचरण करते रहते हैं। सच्चाई यह है कि आलोचना सुनने तथा उसका तार्किक जवाब देने से खुद सरकार का भी गला खुलता है– मोदी इस बात को नहीं समझ पाये क्योंकि उन्होंने विपक्षी नेता की कभी भी सक्रिय भूमिका नहीं निभाई। ज्यादातर वे ऐसे संगठन में रहे जहां सवाल नहीं पूछे जाते। दूसरे, वे हमेशा सत्ता में रहे। पहले गुजरात के मुख्यमंत्री तथा बाद में प्रधानमंत्री। गुजरात में पहले उन्होंने उनके गले घोंटे जिन्होंने वहां भारतीय जनता पार्टी को खड़ा किया थाय फिर उनके घोंटे जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी को बनाया और यहां तक लेकर आये हैं– लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी आदि। फर भी यदि मोदी को लगता है कि उनका गला घोंटा गया है, तो सम्भवतरू उन्होंने इसकी पीड़ा को भी महसूस किया होगा। फिर तो उन्हें यह भी याद होगा कि वे पहले कांग्रेस मुक्त भारत का नारा दे रहे थे जो बाद में सम्पूर्ण श्विपक्ष मुक्त विपक्ष के लक्ष्य में बदल गया। पैसों व जांच एजेंसियों के बल पर कई राज्यों की चुनी हुई सरकारों को गिराकर मतदाताओं के गलों को घोंटा गया। विपक्षी नेताओं की अंधाधुंध गिरफ्तारियां की गईं। पत्रकार, लेखक, मानवाधिकार कार्यकर्ता जेलों में डाले गये हैं जो देश का गला घोंटने से कमतर नहीं है। बहुमत के बल पर पिछली लोकसभा व राज्यसभा के लगभग 150 सदस्य निलम्बित किये गये थे। प्रमुख विपक्षी दल (कांग्रेस) के बैंक खाते सील कर दिये गये। बिना चर्चा के कई तरह के विवादास्पद कानून बनाने का काम भी मोदी जी के कार्यकाल में हुआ है। देश के किसानों से उनके उत्पादों से सम्बन्धित कानूनों पर बात करने की बजाये उन्हें चुपचाप लागू करना और उसका विरोध कर रहे किसानों को दिल्ली तक न पहुंचने देने के लिये उनके रास्तों में खाई खोदना, कीलें ठोंक देना और कड़कड़ाती ठंड में उन पर पानी की बौछारें करना गला घोंटने से कम तो नहीं है। विश्वविद्यालयीन छात्रों की मांगें हों या शाहीन बाग आंदोलन, मजदूरों के मामले हों या फिर आदिवासियों के– गले घोंटने की एक लम्बी प्रक्रिया से गुजरने वाले देश का प्रधानमंत्री अपना गला घोंटने का आरोप लगायें तो उससे अधिक दुखद कुछ भी नहीं हो सकता।

रोजगारोन्मुखी बजट

मोदी सरकार की तीसरी पारी के पहले आम बजट में रोजगार के लक्ष्यों को प्राथमिकता दी गई है। दरअसल, हाल ही के लोकसभा चुनावों में भाजपा के निराशाजनक प्रदर्शन के मूल में रोजगार संकट बड़ी वजह बताया गया। तभी तीसरी पारी के बजट का मूलमंत्र रोजगार सृजन रहा। कहीं न कहीं युवा मतदाताओं को संतुष्ट करने हेतु बजट में नौकरियों व कौशल विकास को प्राथमिकता दी गई है। इसी क्रम में विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार सृजन हेतु योजना लाई गई। महत्वपूर्ण बात यह कि अगले पांच सालों में करीब एक करोड़ युवाओं के कौशल विकास हेतु शीर्ष पांच सौ कंपनियों में इंटर्नशिप के मौके मुहैया कराने की घोषणा की गई। वहीं दूसरी ओर औपचारिक क्षेत्र के कार्यबल का हिस्सा बनने पर युवाओं को एकमुश्त राशि का योगदान भविष्य निधि में किया जाएगा। मोदी सरकार की तीसरी पारी में रोजगार को प्राथमिकता का पता इस बात से चलता है कि पांच योजनाओं के जरिये रोजगार व कौशल विकास के लक्ष्यों को हासिल करने के लिये दो लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। निस्संदेह, कौशल विकास को प्राथमिकता की योजना एक सार्थक कदम है, लेकिन यह सरकार की प्रतिबद्धता व उद्योगों के सहयोग पर निर्भर करेगा। नई नौकरियों की सृजन क्षमता रखने वाले सूक्ष्म,लघु और मध्यम उद्यमों पर बजट में विशेष ध्यान दिया गया। यह प्रयास आत्मनिर्भर भारत की सोच के साथ ही वैश्विक प्रतिस्पर्धा बढ़ाने और नई नौकरियां पैदा करने में सक्षम होगा। कहीं न कहीं अपने मूल मध्यमवर्गीय वोट बैंक के दृष्टिगत वेतनभोगी कर्मियों को कर में राहत व सेवानिवृत्त कर्मियों की पेंशन में मानक आयकर कटौती की सीमा घटाकर संबल दिया गया। इस कदम से चार करोड़ कर्मियों व पेंशनभोगियों का फायदा होने की बात कही जा रही है। वहीं गठबंधन धर्म का पालन करते हुए बिहार व आंध्रप्रदेश के सत्तारूढ़ दलों की आकांक्षा के अनुरूप विशेष वित्तीय पैकेजों की घोषणा अपरिहार्य थी।

बहरहाल, राजग सरकार ने कृषि क्षेत्र के विकास लिये नया रोडमैप इस बजट के माध्यम से देश के सामने रखा है। सरकार की दूसरी पारी में लंबे चले किसान आंदोलन के सबक और नये आंदोलन की सुगबुगाहट के बीच में केंद्र ने किसान व कृषि को अपनी प्राथमिकताओं में रखा है। बजट के जरिये किसानों की आय में स्थिरता, उत्पादकता व आर्थिक विकास के लक्ष्य को हासिल करने पर बल दिया है। खासकर जलवायु परिर्वतन के संकट से जूझती खेती को कवच प्रदान करने की कोशिश है। दो साल के भीतर एक करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती के लिये तैयार करने की योजना है। करीब दस हजार जैव निवेश संसाधन केंद्रों के जरिये प्राकृतिक खेती के लक्ष्यों को पाया जाएगा। हाल के दिनों में प्रतिकूल मौसम व भंडारण केंद्रों के अभाव में उपभोक्ताओं को महंगाई व किसान को नुकसान का सामना करना पड़ा है। इस मकसद से सब्जी उत्पादन बढ़ाने और आपूर्ति शृंखला को सुव्यवस्थित करने हेतु बजट में किसान उत्पादक संगठनों,सहकारी समितियों और स्टार्ट–अप को बढ़ावा देने पर बल दिया गया है। ये संस्थाएं सब्जियों के संग्रहण, भंडारण और विपणन में सार्थक भूमिका निभाते हुए किसानों को बेहतर दाम दिलाने का प्रयास करेंगी। साथ ही फसलों को होने वाला नुकसान कम किया जाएगा। इसके अलावा उन फसलों व बागवानी की किस्मों को बढ़ावा देने का संकल्प है जो जलवायु परिवर्तन के नकारात्मक प्रभाव को निष्प्रभावी बनाकर स्थिर कृषि उत्पादन सुनिश्चित कर सकें। साथ ही तिलहन उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल करने के मकसद से सरसों, मूंगफली, तिल, सोयाबीन व सूरजमुखी की खेती को बढ़ावा देने के उपाय बजट में प्रस्तुत किए गए हैं। जिससे तिलहन उत्पादक किसानों की आय बढ़े तथा आयातित खाद्य तेलों पर देश की निर्भरता को कम किया जा सके। ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिये किसानों की भूमि, ऋण व वित्तीय सेवाओं को चुस्त–दुरुस्त बनाने का प्रयास होगा। इसके बावजूद सरकार को इन योजनाओं के क्रियान्वयन की बाधाओं को प्राथमिकताओं के आधार पर दूर करना होगा। बहरहाल, इस बजट से एक बात तो तय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्राथमिकताओं में बदलाव आया है। वहीं पूंजीगत व्यय में वृद्धि और राजकोषीय घाटा कम करने का प्रयास सराहनीय है।

रोजगार के नए अवसर और आर्थिक विकास को गति देगा आम बजट 2024

हाल ही में लोकसभा के लिए सम्पन्न हुए चुनाव में भारतीय नागरिकों ने लगातार तीसरी बार एनडीए की अगुवाई में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को सत्ता की चाबी आगामी पांच वर्षों के लिए इस उम्मीद के साथ पुनः सौंपी है कि आगे आने वाले पांच वर्षों में केंद्र सरकार द्वारा देश में आर्थिक विकास को और अधिक गति देने के प्रयास जारी रखे जाएंगे। भारत की वित्तमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन ने 23 जुलाई 2024 को मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट भारतीय संसद में पेश किया है। इस बजट के माध्यम से भारत की आर्थिक विकास दर को उच्च स्तर पर ले जाने का प्रयास किया गया है।

केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए 9 प्राथमिकताएं तय की है। कृषि क्षेत्र में उत्पादकता को बढ़ाना, युवाओं के लिए रोजगार के अधिकतम अवसर निर्मित करना एवं उनके कौशल को विकसित करना, गरीब नागरिकों को भी विकास में हिस्सेदारी देना एवं उन्हें सामाजिक न्याय देना, विनिर्माण इकाईयों को बढ़ावा देना, शहरी क्षेत्रों को विकसित करना, ऊर्जा की उपलब्धता सुनिश्चित करना, आधारभूत ढांचा विकसित करना, नवाचार, शोध एवं विकास करना तथा नई पीढ़ी के सुधार कार्यक्रमों को लागू करना। केंद्र सरकार एवं कुछ राज्य सरकारों द्वारा पूंजीगत खर्चों में लगातार की जा रही वृद्धि के चलते भारत की आर्थिक विकास दर को पंख लगते दिखाई दे रहे हैं। वर्ष 2022–23 के बजट में केंद्र सरकार द्वारा 7.5 लाख करोड़ रुपए के पूंजीगत खर्चों का प्रावधान किया गया था, वित्तीय वर्ष 2023–24 में इसमें 33 प्रतिशत की भारी भरकम वृद्धि करते हुए इसे बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपए का कर दिया गया था। अब वित्तीय वर्ष 2024–45 के लिए इसे और आगे बढ़कर 11.11 लाख करोड़ रुपए का कर दिया गया है, जो भारत के सकल घरेलू उत्पाद का 3.4 प्रतिशत है। इससे भारतीय अर्थव्यवस्था में न केवल स्थिरता दिखाई देने लगी है बल्कि यह लगातार तेज गति से आगे बढ़ रही है। आज पूरे विश्व में केवल भारतीय अर्थव्यवस्था ही एक चमकते सितारे के रूप में दिखाई दे रही है।

बजट का गहराई से अध्ययन करने पर ध्यान में आता है कि केंद्र सरकार ने अब भारत में रोजगार के अधिकतम अवसर निर्मित करने की ठान ली है। भारत के युवाओं एवं महिलाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने एवं कौशल विकसित करने की दृष्टि से 2 लाख करोड़ रुपए की 5 योजनाओं के एक पैकेज की घोषणा की है। शिक्षा, रोजगार एवं कौशल विकास के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपए की राशि इस बजट में आबंटित भी कर दी गई है। प्रधानमंत्री पैकेज के अंतर्गत EPFO के प्रथम बार सदस्य बनने पर औपचारिक क्षेत्र के कर्मचारियों के EPFO खातों में एक माह का वेतन जमा किया जाएगा। इन कर्मचारियों को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण योजना के अंतर्गत एक माह का वेतन (15000 रुपए की अधिकतम राशि तक) तीन किश्तों में उनके खातों में जमा किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत एक माह में एक लाख रुपए तक का वेतन पाने वाली कर्मचारी ही पात्र होंगे। इससे 2.1 करोड़ युवाओं को लाभ होने की सम्भावना बजट में व्यक्त की गई है।

ऐसे भी कई निर्णय लिए जा रहे हैं जिनसे आने वाले समय में धरातल पर युवाओं को लाभ होता दिखाई देगा। एक करोड़ युवाओं को आगामी 5 वर्षों के दौरान इंटर्नशिप योजना के अंतर्गत काम दिया जाएगा। ताकि ये युवा वर्ग के नागरिक रोजगार प्राप्त करने हेतु सक्षम हो सकें। इन युवाओं को प्रति माह 6,000 रुपए तक का वाजीफा सम्बंधित कम्पनियों द्वारा अदा किया जाएगा। वजीफे की इस राशि को कम्पनियों के लिए लागू निगमित सामाजिक दायित्व योजना के अंतर्गत किया गया खर्च माना जाएगा। भारत की सबसे बड़ी 500 कम्पनियों को इस योजना के अंतर्गत युवाओं को इंटर्नशिप की सुविधा देनी होगी। साथ ही, केंद्र सरकार द्वारा भी इन युवाओं को प्रतिमाह 5000 रुपए अदा किए जाएंगे। यह केंद्र सरकार का एक सूझबूझ भरा निर्णय कहा जा सकता हैं। साथ ही, विनिर्माण के क्षेत्र के रोजगार के नए अवसर निर्मित करने की पहल भी की जा रही है। नए कर्मचारियों के EPFO खाते में जमा होने वाली राशि को आगामी 4 वर्षों तक केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाएगा, इससे कर्मचारी एवं नियोक्ता दोनों को ही लाभ होगा। इस योजना का लाभ 30 लाख युवाओं को होने जा रहा है। एक अन्य योजना के अंतर्गत नियोक्ता को अपने नए कर्मचारियों के EPFO खातों में जमा की जाने वाली राशि की प्रतिपूर्ति आगामी 2 वर्षों तक केंद्र सरकार द्वारा की जाएगी। इससे रोजगार के 50 लाख नए अवसर निर्मित होने की सम्भावना है।

केंद्र सरकार द्वारा हाल ही के समय में भारतीय सनातन संस्कृति के संस्कारों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से धार्मिक पर्यटन को देश में बढ़ावा दिया जा रहा है। धार्मिक पर्यटन से देश में रोजगार के लाखों अवसर निर्मित हो रहे हैं एवं गरीब वर्ग की आय में बेतहाशा वृद्धि हो रही है। श्री विष्णुपाद मंदिर कोरिडोर, गया, बिहार एवं श्री महाबोधि मंदिर कोरिडोर बोधगया, बिहार को विकसित किए जाने की घोषणा की गई है। इसे काशी विश्वनाथ मंदिर कोरिडोर की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। इसी प्रकार देश में अन्य मंदिरों को भी विकसित किया जा रहा है ताकि देश में इन मंदिरों में श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो तथा भारत को वैश्विक पटल पर एक बहुत बड़े धार्मिक पर्यटन केंद्र के रूप में दिखाया जा सके।

भारत के ग्रामों में निवास कर रहे नागरिक रोजगार प्राप्त करने के उद्देश्य से शहरों की ओर पलायन करते हैं। अतः ग्रामों में ही रोजगार के अधिकतम अवसर निर्मित करने के उद्देश्य से ग्रामीण विकास की मद पर 2.66 लाख करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान इस बजट में किया गया है। साथ ही, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मुद्रा लोन योजना के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली ऋण राशि की सीमा को 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दिया गया है। यह सुविधा तरुण श्रेणी के अंतर्गत प्राप्त ऋण के व्यवसाईयों को प्राप्त होगी एवं जिन्होंने पूर्व में लिए गए 10 लाख रुपए के ऋण की राशि को समय पर अदा कर दिया है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों के लिए भी ऋण की सीमा को बढ़ाकर 100 करोड़ रुपए तक कर दिया गया है।

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत एक करोड़ आवासों का निर्माण किया जाएगा। इन एक करोड़ आवासों पर 10 लाख करोड़ रुपए की राशि का निवेश होगा, इसमें केंद्र सरकार की भागीदारी 2.2 लाख करोड़ रुपए की रहेगी। साथ ही, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत 3 करोड़ आवासों का निर्माण करने की घोषणा पूर्व में ही की जा चुकी है। देश के आर्थिक चक्र को गति देने के उद्देश्य से नई कर प्रणाली के अंतर्गत वेतनभोगी/पेंशनधारी कर्मचारियों के लिए सामान्य छूट की सीमा को 50,000 रुपए से बढ़ाकर 75,000 रुपए कर दिया गया है। साथ ही, आय कर की दरों में कुछ इस प्रकार का संशोधन किया गया है कि 15 लाख रुपए तक की कर योग्य आय वाले कर्मचारियों को प्रतिवर्ष 17,500 रुपए का लाभ होगा। इस निर्णय से मध्यम वर्गीय नागरिकों के हाथों में कुछ अधिक राशि बचेगी और इस राशि इस इनकी क्रय शक्ति बढ़ेगी ताकि देश की अर्थव्यवस्था के चक्र में मजबूती आएगी।

वित्तीय वर्ष 2024–25 के बजट में कुल आय का अनुमान रुपए 31.07 लाख करोड़ रुपए का लगाया गया है, इसमें ऋण की राशि शामिल नहीं है परंतु, करों के मद से प्राप्त होने वाली 25.83 लाख करोड़ रुपए की राशि शामिल है। जबकि, कुल खर्च का अनुमान 48.21 लाख करोड़ रुपए का लगाया गया है।

जनपद उन्नाव में कई वर्षों से सर्वे कार्य लटका उन्नाव के सिकंदरपुर करण ब्लॉक के कटरी पीपरखेड़ा ग्राम सभा में भूमि धरी किसान अपने अभिलेख लेकर इधर-उधर भटक रहे।

उन्नाव। उन्नाव के सिकंदरपुर ब्लॉक के कटरी पीपलखेड़ा ग्राम सभा में सर्वे कार्य पूरा करने के आदेश जारी हुए थे। कई बार कार्यवाही शुरू हुई लेकिन कार्य पूरा नहीं हो सका ग्राम सभा के हजारों किसान अपनी जमीन की बजाय दूसरी जगह पर काबिज है। इस वक्त काश्तकारी जमीनों पर आलीशान मकान खड़े हुए है। कई वर्ष पूर्व ग्राम सभा में सर्वे कार्य के लिए जिला प्रशासन ने सहायक अभिलेख अधिकारी को जिम्मेदारी दी थी। इसके बाद विभाग के जिम्मेदारों ने कोई ध्यान नहीं दिया। भूमि धरी किसान अपने अभिलेख लेकर इधर–उधर भटक रहे हैं। जिसे जहां मौका मिला कब्जा जमा लिया। अपने मूल नंबर पर कोई भी किसान काबिज नहीं है। सर्वे विभाग किसानों को टहलता है। क्षेत्रीय लोगों ने संबंधित अधिकारी व सत्ता पक्ष के जिम्मेदारों को अवगत कराया है। सूत्रों के मुताबिक आज भी और पूर्व से जमीन क्रय विक्रय कर मलाई खाने वाले कुछ लोग छोटी जनता को दबाकर जमीनों की प्लाटिंग और क्रय विक्रय कर रहे हैं संबंधित राजस्व विभाग मौन बैठा है। सूत्रों के मुताबिक राजस्व विभाग के कुछ कर्मचारी सर्वे क्षेत्र में ही अपनी पोस्टिंग चाहते हैं ऐसा क्यों सूत्रों के मुताबिक पुलिस विभाग के कुछ ऐसे कर्मचारी हैं जो केवल कटरी पीपलखेड़ा चौकी जाजमऊ के क्षेत्र के अंतर्गत रहकर ही नौकरी करना चाहते हैं इस बात पर क्षेत्र में जगह–जगह चर्चा है।

बांग्लादेश से लाईं जा रहीं युवतियों का ट्रेनिंग सेंटर बना कानपुर, जेल में बंद नाजमा से पूछताछ में खुलासा

सूत्रों के अनुसार जांच में पता चला है कि दिल्ली की एजेंसियां ही इन युवतियों की फेंक आईडी बनवा रही है। साथ ही मोटा कमीशन लेकर घरों में कामकाज के लिए इन्हें भेजा जाता है। पकड़ी गई बांग्लादेशी युवती अखीमुंशी उर्फ मधू सिंह के पास भी आधार कार्ड और पैन कार्ड बरामद हुआ है।

कानपुर। कानपुर में कल्याणपुर से पकड़ी गई बांग्लादेशी युवती नाजमा से पूछताछ में बांग्लादेश से दिल्ली और देश के अन्य शहरों के बीच चल रहे मानव तस्करी के

काले कारोबार और कानपुर को बतौर ट्रेनिंग सेंटर इस्तेमाल करने की बात सामने आई है। पता चला है कि हर साल सैकड़ों लड़कियां बांग्लादेश से घरेलू काम के नाम पर भारत पहुंचाई जा रही हैं। दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े शहरों में एंट्री ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल की सख्ती के चलते लड़कियों को कानपुर लाकर कुछ समय के लिए रखा जाता है। यहां घरेलू कामकाज की ट्रेनिंग लेती हैं। इस बीच वह अपनी नई पहचान और दस्तावेज बनने व नौकरी मिलने का इंतजार करती हैं। इसके बाद ज्योति निषाद जैसी युवतियों को उन्हें एजेंसियों तक पहुंचाने का जिम्मा सौंपा जाता है।

दरअसल, नाजमा ने पूछताछ के दौरान अधिकारियों को बताया कि पकड़ी गई दिल्ली निवासी ज्योति निषाद एक ऐसी ही एजेंसी के साथ जुड़ी हुई है। पकड़े जाने वाले दिन वह दिल्ली ले जाने के लिए ही कानपुर आई थी, जहां उसे नए नाम व नई पहचान से जुड़े दस्तावेज के साथ काम दिलाया जाना था। हालांकि उससे पहले ही पुलिस ने उसे पकड़ लिया।

नई पहचान के साथ अलग–अलग शहरों में रह रही हैं युवतियां

सूत्रों की मानें, तो पूछताछ में ऐसी कई युवतियों का पता चला है कि जो इसी तरीके से भारत में दाखिल हुई और अब नई पहचान के साथ देश के अलग–अलग शहरों में रह रही हैं। अधिकारियों का मानना है कि दूसरे देश से आने वाली महिलाओं का इस्तेमाल हनी ट्रैप से लेकर किसी भी तरह की गतिविधि के लिए हो सकता है। साथ ही ऐसे रास्ते का दुरुपयोग देश विरोधी गतिविधि के लिए होने का खतरा है, इसलिए राष्ट्रीय सुरक्षा व खुफिया एजेंसियां भी सक्रिय हो गई हैं। वहीं, देह व्यापार के एंगल से भी जांच की जा रही है।

एजेंसियां बनवा रही फर्जी आधार

सूत्रों के अनुसार जांच में पता चला है कि दिल्ली की एजेंसियां ही इन युवतियों की फेंक आईडी बनवा रही है। साथ ही मोटा कमीशन लेकर घरों में कामकाज के लिए इन्हें भेजा जाता है। पकड़ी गई बांग्लादेशी युवती अखीमुंशी उर्फ मधू सिंह के पास भी आधार कार्ड और पैन कार्ड बरामद हुआ है। पुलिस ने पैन और आधार बनने की जांच कर रही है। अखीमुंशी और नाजमा से पूछताछ की गई है। कुछ जानकारियां मिली हैं जिन्हें तस्दीक करने के लिए पुलिस की टीम कोलकाता, दिल्ली जाएगी। अखीमुंशी से भी पूछताछ की जा रही है।

मां ने पांच साल के बेटे को फंदे से लटकाया, फिर खुद भी कर ली आत्महत्या, परिजन बोले- कलह में उठाया कदम

अजगैन कोतवाली क्षेत्र में मां ने पांच साल के बेटे को फंदे से लटकाकर मार डाला। इसके बाद खुद भी आत्महत्या कर ली। मायके पक्ष ने ससुरालियों पर हत्या का आरोप लगाया है।

उन्नाव। उन्नाव जिले के अजगैन कोतवाली क्षेत्र में पारिवारिक कलह से परेशान महिला ने पांच साल के बच्चे को फंदे से लटकाने के खुद भी आत्महत्या कर ली। मृतका के मायके वालों ने ससुरालीजनों पर हत्या का आरोप लगाया है। घटना से इलाके में हड़कंप मच गया है। अजगैन कोतवाली के मलांव गांव निवासी देशराज की पत्नी शांति (30) ने गुरुवार सुबह करीब छह बजे पारिवारिक कलह में पहले बेटे देवराज (5) को फंदे पर लटका कर मार डाला। फिर खुद साड़ी के फंदे से लटककर आत्महत्या कर ली।

पति देशराज साड़ी के दोनों छोर में पहले बच्चे और फिर पत्नी का शव लटका देख बेहाल हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की है। पुलिस को देशराज ने बताया कि पहले वह मुंबई में रहकर मजदूरी करता था। पांच महीने पहले वह घर आ गया था।

पति–पत्नी में अक्सर होता था विवाद

तब से यहीं मजदूरी कर पालन पोषण करता था। मोहल्लेवासियों के मुताबिक, शांति का अक्सर सास गुड्डी की सेवा न करने पर पति से विवाद होता था। देशराज तीन भाई है। सब अलग–अलग रहते हैं। मां के साथ पत्नी का व्यवहार देख देशराज अक्सर पत्नी को पीटता था।

मायके वालों ने ससुरालियों पर हत्या का आरोप लगाया

इससे दोनों में जमकर विवाद होता था। पुलिस ने पति और मोहल्ले वालों के बयान दर्ज किए हैं। सूचना पर दही थानाक्षेत्र के शिवदीनखेड़ा निवासी मृतका के मायके वालों ने ससुरालियों पर हत्या का आरोप लगा हंगामा किया।

शव पोस्टमार्टम के लिए भेजे

कोतवाल ने परिजनों को पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई का शासन दिया, तब परिजन शांत हुए। कोतवाल अवनीश सिंह ने बताया कि पारिवारिक विवाद में मां ने बेटे को फंदे से लटकाने के बाद खुद भी आत्महत्या की है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट कराया जा रहा है।

गंदगी देख भड़कीं कमिश्नर फोन पर अधिकारियों को लगाई फटकार

लखनऊ। लखनऊ में दस्तक अभियान की हकीकत जानने के लिए निकलीं मंडलायुक्त रोशन जैकब अव्यवस्था देख भड़क गईं। आलमबाग के गीतापल्ली में नालियों में शिल्ट जमी हुई मिली। कई जगहों पर नालियां टूटी और चोक मिलीं। इसपर रोशन जैकब ने जोनल अधिकारी नंदकिशोर और जेएड एसओ राजेश को फोन पर फटकार लगाई। मंडलायुक्त ने अपर नगर आयुक्त को निर्देश दिया कि सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा हटाया जाए। लोगों ने कमिश्नर रोशन जैकब को बताया कि कई दिनों से यह समस्या बनी हुई है। मंडलायुक्त ने नालियों में जमी शिल्ट को हटाने के निर्देश दिए। रोशन जैकब ने कहा– एंटी लार्वा की फॉगिंग कराई जाए, टूटे–फूटे नालियों की मरम्मत हो, खुले में कूड़ा डंप ना होने पाए साथ ही कूड़े की शिफ्टिंग का काम समय पर किया जाए। रोशन जैकब ने घरों का दौरा कर दिमागी बुखार, जलजनित रोग के रोकथाम और उपचार के लिए लोगो को जागरूक किया। उन्होंने बताया कि इस अभियान के तहत बच्चों को दस्त रोग, निमोनिया और जन्मजात बिमारियों से पीड़ित बच्चों की पहचान कर उन्हें निःशुल्क जांच एवं उपचार तथा परिवहन सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। इस अभियान के तहत पांच साल से कम उम्र के सभी बच्चों की खून की कमी की जांच, छः माह से पांच वर्ष तक के गंभीर कुपोषित बच्चों की पहचान और 9 माह से 5 वर्ष तक के बच्चों को विटामिन 'ए' का घोल दिया जाना है। अरविंद कुमार निगम ने कहा कि मिटौली क्रॉसिंग के पास न्याय बिहार कॉलोनी में स्ट्रीट लाइट की समस्या का हल नहीं निकला है। कर्मचारी आए भी तो दो लाइट सही कर चले गए। खुद के पैसे से 9 स्ट्रीट लाइट लगवाई गई। 10 खंभों में कोई भी स्ट्रीट लाइट नहीं लगी है। उसके लिए ही निवेदन किया गया था।

नीट-यूजी परीक्षा कराने में अब तक विफल रही सरकार, पुरानी व्यवस्था क्यों न बहाल हो : मायावती

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री बसपा सुप्रीमो मायावती ने नीट–यूजी मेडिकल परीक्षा में हुई गड़बड़ी को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने एक्स पर लिखा आल–इंडिया नीट–यूजी मेडिकल परीक्षा में हुई गड़बड़ी को लेकर स्वाभाविक तौर पर सड़क से लेकर संसद व सुप्रीम कोर्ट तक में यह

मामला गरमाया रहा। अब नतीजा चाहे जो भी हो, लेकिन लाखों परीक्षार्थियों व उनके परिवार वालों को इसको लेकर हुआ दुःख–दर्द व मानसिक पीड़ा हमेशा सताएगी। उन्होंने अपने दूसरे पोस्ट में लिखा केन्द्र मेडिकल की इतनी अहम परीक्षा सही से कराने के मामले में देश को आश्वस्त कर पाने में अभी तक विफल है जो समस्या को और गंभीर बना रहा है। अतः केन्द्रीयकृत मेडिकल नीट यूजी–पीजी परीक्षा को समाप्त कर इसके लिए पुनः पुरानी व्यवस्था क्यों न बहाल हो, जैसाकि कई राज्य सरकारों की मांग है। आप को बता दें कि नीट–यूजी 2024 के असफल अभ्यर्थियों को उच्चतम न्यायालय ने बड़ा झटका देते हुए मंगलवार को उन याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिनमें विवादों में घिरी इस परीक्षा को रद्द कर दोबारा आयोजित कराने की मांग की गई थी। इसके साथ ही न्यायालय ने कहा कि इसकी शुचिता से समझौता होने और अन्य गड़बड़ियों को दर्शाने वाली कोई सामग्री रिकॉर्ड में नहीं है। न्यायालय का यह अंतरिम फैसला है और बाद में विस्तृत फैसला सुनाया जाएगा। इस अंतरिम फैसले से केंद्र सरकार और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) को बड़ी राहत मिली है, जो पांच मई को संपन्न परीक्षा में प्रश्नपत्र लीक सहित बड़े पैमाने पर कथित गड़बड़ी को लेकर सड़क से संसद तक कड़ी आलोचना एवं विरोध का सामना कर रही है।

अमुवि कुलपति द्वारा छात्रावासों के निरीक्षण का सप्ताह भर का दौर संपन्न

अलीगढ। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की कुलपति प्रो. नईमा खातून द्वारा छात्रावासों की सफाई और रखरखाव के निरीक्षण का एक सप्ताह पर आधारित कार्यक्रम आज संपन्न हो गया। एएमयू की कुलपति के रूप में पदभार ग्रहण करने के बाद से, प्रोफेसर नईमा खातून की प्राथमिकता छात्रावासों को पूर्ण रूप से खाली कराकर छात्रों की आसानी के लिए आवासीय हालों की सफाई और रखरखाव और उनका जीर्णोद्धार रहा है ताकि छात्रों को रहने का बेहतर अनुभव हो सके। यह अभियान गर्मी की छुट्टियों के दौरान जारी रहा और कुलपति ने छात्रावासों की सफाई, रखरखाव और रहने की स्थिति से संबंधित अन्य व्यवस्थाओं का आकलन करने के लिए विभिन्न हालों का 18 से 24 जुलाई 2024 तक निरीक्षण किया। इस प्रक्रिया में सुलेमान हॉल, आफताब हॉल, सर जियाउद्दीन हॉल, बीबी फातिमा हॉल, एसएन हॉल, एसएस हॉल (उत्तर), एसएस हॉल (दक्षिण), आरएम हॉल, एमएम हॉल, अब्दुल्ला हॉल, आईजी हॉल, बीएसजे हॉल, बीआर अंबेडकर हॉल, हादी हसन हॉल, बेगम अजीज–उन–निसा हॉल, वीएम हॉल, हबीब हॉल और नदीम तरीन हॉल सहित सभी आवासीय हॉल का गहन निरीक्षण किया गया। उन्होंने प्रत्येक डाइनिंग हॉल, कॉमन रूम, रीडिंग रूम और कई शौचालय क्षेत्रों के साथ–साथ छात्रों के अन्य संबंधित सामान्य उपयोग वाले स्थानों का निरीक्षण किया। प्रो. खातून ने रजिस्ट्रार, वित्त कार्यालय, प्रॉक्टर, डीएसडब्ल्यू और भवन, संरक्षण, बिजली, भूमि और उद्यान और स्वास्थ्य विभाग के मेंबर इंचार्जों सहित सभी संबंधित अधिकारियों के साथ छात्रावासों का निरीक्षण किया। पुरानी इमारतों में रिसाव और प्लास्टर उखड़ने जैसी समस्याओं को इंगित किया गया और भवन निर्माण विभाग को प्राथमिकता के रूप में उनका ध्यान रखने का निर्देश दिया गया। सर सैयद हॉल (उत्तर और दक्षिण) में स्थित ऐतिहासिक इमारतों के संरक्षण के लिए भवन निर्माण विभाग को विशेष प्रयास करने के लिए कहा गया। प्रो. खातून ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि वे आवासीय हॉल में रहने वालों के लिए अनुकूल माहौल बनाने के लिए स्थितियों में सुधार करें, खासकर डाइनिंग हॉल, शौचालय, रसोई, कॉमन रूम और पढ़ने के कमरे जैसे सामान्य उपयोग वाले स्थानों आदि पर विशेष ध्यान दिया जाये।उन्होंने कहा कि अधिकांश आवासीय हॉल में महत्वपूर्ण सुधार हुए हैं, लेकिन अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है और यह काम अभी भी जारी है। उन्होंने जोर देकर कहा कि केवल वास्तविक छात्र ही छात्रावासों में रहने की सुविधा का लाभ उठाते हैं। उन्होंने विश्वविद्यालय परिसर में आवासीय जीवन को बेहतर बनाने के इस प्रमुख कार्य में छात्र समुदाय द्वारा दिए गए सहयोग का विशेष उल्लेख किया। उन्होंने इस प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए हॉल के निवासियों की सराहना की, जिसका नए शैक्षणिक सत्र में उनके रहने की स्थिति पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।उन्होंने गैर–शिक्षण कर्मचारियों द्वारा की गई कड़ी मेहनत की भी सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने खुद को छात्रों की भलाई के लिए प्रतिबद्ध किया है और इसके लिए उन्होंने सभी हितधारकों से परिसर को साफ–सुथरा रखने और इसे नियमित अभ्यास के रूप में बनाए रखने की इस प्रक्रिया को जारी रखने का आग्रह किया है।

राष्ट्रीय लोक अदालत में आकर शीघ्र, सुलभ व सक्षम न्याय पायें

अवध की आवाज ब्यूरो

उन्नाव। जन सामान्य को त्वरित, सस्ता एवं सुलभ न्याय उपलब्ध कराने हेतु आगामी 13 सितम्बर 2024 दिन शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। उक्त राष्ट्रीय लोक अदालत के दृष्टिगत माननीय जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उन्नाव श्रीमती प्रतिमा श्रीवास्तव के निर्देशानुसार अपर जिला जज/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, उन्नाव श्री मनीष निगम द्वारा बताया गया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में तहसील न्यायालय से लेकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के स्तर पर किसी भी न्यायालय अथवा विभागीय मामलों को सुलह–समझौते के आधार पर निस्तारित किए जाने हेतु आवेदन पत्र देकर अन्तिम आदेश व निर्णय प्राप्त कर सदैव के लिए लम्बित मामले से छुटकारा पाया जा सकता है। उन्होने जानकारी देते हुए कहा कि लोक अदालत में पक्षो के मध्य आपसी सुलह–समझौते के आधार पर विवाद का निस्तारण पक्षकार–व्यक्तिगत स्तर पर स्वयं पहल कर सकते हैं। लोक अदालत में वाद निस्तारण हेतु किसी भी प्रकार का शुल्क देय नहीं है। लम्बित मामले के लोक अदालत में निस्तारण पर न्यायालय शुल्क वापसी की व्यवस्था है। इसके निर्णय के विरूद्ध कोई अपील नहीं की जा सकती है। कानूनी जटिलताओ से परे लोक अदालत की प्रक्रिया सहज और आपसी समझौते पर आधारित है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में सभी प्रकार के शमनीय आपराधिक/सुलह सुमझौते से निस्तारित होने वाले वाद, उत्तराधिकार से संबंधित सिविल मामले, वाद वापसी के मामले, बैंक ऋण वसूली प्री–लिटिगेशन वाद, पारिवारिक एवं वैवाहिक मामले, नगर निगम/नगर पालिका अधिनियम, श्रम संबंधी वाद, भूमि अधिग्रहण संबंधी मामले, राजस्व संबंधित मामले, सर्विस मैटर्स, मनरेगा वाद, व्यापार कर वाद, वजन व मापतौल अधिनियम, वन अधिनियम, उपभोक्ता फोरम वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, एन0आई0एक्ट के वाद, विद्युत एवं जल संबंधी अन्य वाद, आरबीटेशन वाद, आपदा राहत वाद, यातायात चालानी वाद आदि का निस्तारण कराया जा सकता है। जनपद वासियों से अपील है कि यदि आप किसी भी लम्बित वाद को राष्ट्रीय लोक अदालत में सुलह–समझौते के आधार पर निस्तारित कराना चहते है, तो कृपया संबंधित न्यायालय के पीठासीन अधिकारी अथवा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उन्नाव के कार्यालय से सम्पर्क कर अपने वाद को राष्ट्रीय लोक अदालत में नियत करा सकते है।

कुल्हाड़ी से युवक के पैर काटे,वर्चस्व की जंग में दो भाइयों पर किया जानलेवा हमला

अलीगढ। अलीगढ़ के इगलास थाना क्षेत्र के दुमेड़ी में वर्चस्व की जंग में एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के कुल्हाड़ी से दोनों पैर काट दिए। पीड़ित युवक अपने भाई के साथ जा रहा था, तभी 4–5 आरोपियों ने उसे घेर लिया और फायरिंग शुरू कर दी। गोली चलते देख पीड़ित का भाई वहां से भाग निकला। जिसके बाद आरोपियों ने पीड़ित को पकड़ लिया और उसके साथ जमकर मारपीट की। आरोप है कि मारपीट करने के बाद हमलावरों ने कुल्हाड़ी से उसके दोनों पैरों पर हमला बोल दिया और उसके पैर काट दिया। गोली चलने और हंगामा होने पर पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। लोगों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद क्षेत्रिय पुलिस तत्काल मौके पर पहुंच गई। इगलास थाना क्षेत्र के गांव दुमेड़ी निवासी मनोज उर्फ मन्ना गुरुवार को अपने भाई के साथ खेत में पानी लगाने गया था। खेत में पानी लगाने के बाद दोनों भाई बाइक से घर लौट रहे थे। इसी दौरान 4–5 आरोपियों ने उनकी बाइक रोक ली। आरोप है कि हमलावरों ने बाइक रोकने के बाद फायरिंग शुरू कर दी। मन्ना बाइक चला रहा था और उसका भाई पीछे बैठा था। फायरिंग होते देख मन्ना का भाई मौके से जान बचाकर भाग निकला। वहीं आरोपियों ने मन्ना को पकड़ लिया और उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। फिर आरोपियों ने उसके पैर काट दिए और उसे मरणासन्न अवस्था में मौके पर ही छोड़कर भाग गए। पुलिस ने घायल को सीएचसी पहुंचाया, जहां से उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। घायल मनोज पर हमला करने वाले आरोपी उसके गांव दुमेड़ी के ही बताए जा रहे हैं। दोनों पक्षों के बीच में वर्चस्व की जंग चल रही है और कई बार दोनों के बीच विवाद हो चुका है। जिसके चलते दोनों पक्षों ने एक दूसरे के ऊपर कई मुकदमें दर्ज करवा रखे हैं। पीड़ित पक्ष ने बताया कि आरोपी लगातार मुकदमों में समझौता करने का दबाव बना रहे थे और पिछले कई दिनों से धमकी भी दे रहे थे। जब उन लोगों ने आरोपियों की बात नहीं सुनी तो गुरुवार को आरोपियों ने मनोज के ऊपर जानलेवा हमला कर दिया। वहीं पुलिस घटना के बाद मामले की जांच में जुट गई है।घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी तत्काल मौके से फरार हो गए। वहीं दूसरी ओर घायल को अस्पताल में भर्ती कराने के बाद पुलिस आरोपियों की तलाश में दबिश दे रही है, जिससे कि उन्हें गिरफ्तार किया जा सके। घायल पक्ष की ओर से अभी पुलिस को कोई तहरीर नहीं मिली है। सीओ इगलास डॉ कृष्ण गोपाल ने बताया कि कोतवाली में दोनों पक्षों के ऊपर कई मुकदमें दर्ज हैं। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और घटना स्थल की जांच की जा रही है। उन्होंने बताया कि पीड़ित पक्ष से तहरीर प्राप्त की जा रही है, जिसके बाद मुकदमा दर्ज किया जाएगा। आरोपियों की तलाश में दबिश जारी है और जल्दी ही वह हिरासत में होंगे।

हिंदूवादी संगठनों ने एसपी ऑफिस का किया घेराव,थानाध्यक्ष समेत 3 लाइन हाजिर

बांदा। जनपद में लव जेहाद और धर्मांतरण का विरोध करना बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को भारी पड़ गया। पुलिस ने थाने के अंदर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को जमकर पीटा था। देर रात नाराज हिंदू संगठनों के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने पुलिस अधीक्षक आवास के बाहर जमकर की नारेबाजी और पुलिस अधीक्षक का पुतला फूंकने का प्रयास किया था। आवास के बाहर पुलिस के अधिकारियों ने पहुंचकर कार्यकर्ताओं को समझाने का प्रयास किया था। नाराज कार्यकर्ता दोषी थानाध्यक्ष और पुलिस कर्मियों के निलंबन को लेकर अड़े रहे थे। मौके पर पहुंचे अपर पुलिस अधीक्षक ने पूरे मामले की जांच कर कार्यवाही कराने का भरोसा दिलाया था। आज दोपहर में फिर एक बार हिंदू संगठनों ने एसपी ऑफिस का घेराव किया। जहां पर पुलिस अधीक्षक से काफी देर बात करने के बाद पुलिस अधीक्षक ने तिंदवारी थाना प्रभारी समेत दो कॉन्स्टेबल को लाइन हाजिर कर दिया है और जांच के आदेश दिए हैं। मामला तिंदवारी थाने का है जहां पर नाबालिक लड़की के साथ लव जेहाद कर धर्मांतरण का मामला था। जिसको लेकर बजरंग दल व विश्वहिंदू परिषद के कार्यकर्ता थाने में पहुंचकर थानाध्यक्ष से विरोध जताया था। जिसको लेकर थानाध्यक्ष ओर कार्यकर्ताओं के बीच कहासुनी हो गई। इसी दौरान पुलिस ने बजरंग दल के दो कार्यकर्ताओं की जमकर पिटाई कर दी। नाराज कार्यकर्ता देर रात पुलिस अधीक्षक के आवास पर पहुंचकर पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और पुलिस अधीक्षक का पुतला फूंकने का प्रयास किया। आज फिर एक बार हिंदू संगठनों ने एसपी ऑफिस का घेराव किया। जहां पर दोनों के बीच काफी देर तक बात चली। पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल ने तिंदवारी थानाध्यक्ष सहित 2 कॉन्स्टेबल को लाइन हाजिर कर दिया और मेडिकल करवाने की बात कही। उन्होंने कहा कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पति ने हेडमास्टर को पीटा

अलीगढ़। अलीगढ़ के विजयगढ़ थाना क्षेत्र के गांव नगला सुक्का में एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पति ने गुरुवार को प्राथमिक विद्यालय के हेडमास्टर के साथ मारपीट की। आरोपी ने अपने भाई को भी साथ बुला लिया और हेडमास्टर पर हमला कर दिया। हंगामा होते देख गांव के लोग भी मौके पर पहुंच गए और उन्होंने बीच बचाव करके हेड मास्टर की जान बचाई। जिसके बाद पीड़ित हेडमास्टर ने तत्काल पुलिस को सूचना दी और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। वहीं पुलिस ने घायल हेडमास्टर को मेडिकल परीक्षण कराया है और कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। अकराबाद ब्लाक के प्राथमिक विद्यालय नगला सुक्का के इंचार्ज हेडमास्टर अविनाश कुमार ने बताया कि वह गुरुवार को स्कूल में बच्चों को पढ़ा रहे थे। तभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का पति स्कूल में आ गया और अपनी पत्नी से तेज आवाज में जोर–जोर से बात करने लगा। जिसके बाद हेडमास्टर ने उसे बुलाया और कहा कि वह स्कूल में इस तरह से बात न करे, क्योंकि इससे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होती है। इसके साथ ही उन्होंने उसे स्कूल समय के दौरान वहां आने से मना किया और कहा कि अपनी पत्नी के घर आने के बाद अपनी घरेलू बातचीत किया करे। जिसके बाद आरोपी आक्रामक हो गया और गाली गलौज करने लगा। पीड़ित हेडमास्टर ने बताया कि आरोपी पहले अपशब्द बोलने लगा और फिर अपने भाई को बुलाकर उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। दोनों भाइयों ने कैंपस के अंदर ही उनके साथ जमकर मारपीट की। जिससे उन्हें चोटें भी आई हैं। घटना के दौरान कुछ लोगों ने मारपीट का वीडियो भी बना लिया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। विजयगढ़ थाना प्रभारी ने बताया कि हेडमास्टर की तहरीर मिली है। उनका मेडिकल परीक्षण कराया गया है और तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

कारगिल विजय दिवस, रजत जयंती पर प्रदर्शनी और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन

गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने ''कारगिल जागरुकता रथों'' को दिखाई हरी झंडी

लखनऊ। कारगिल विजय दिवस के रजत जयंती पर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा देश भर में कार्यक्रमों का आयोजन कर कारगिल युद् में शहीद हुए वीर योद्दाओं को याद किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में केंद्रीय संचार ब्यूरों द्वारा 12 स्थानों पर गोष्ठी, रैली, व्याख्यान और विभिन्न प्रतियोगितायें एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं जिससे देश की युवा पीढी अपने शहीदों की वीर गाथा को जान सके। कार्यक्रम की पूर्व संध्या पर आज लखनऊ के केंद्रीय भवन में गृह मंत्रालय तथा सूचना एवम प्रसारण मंत्रालय के इकाईयों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने शहीदों को नमन किया। इस अवसर पर गृह मंत्रालय के शत्रु संपत्ति अभिरक्षक कार्यालय लखनऊ के उपसचिव राजेंद्र कुमार ने अपने साथी अधिकारियों ब्रिगेडियर सेनि अरबिंदम और ब्रिगेडियर सेनि यशपाल सिंह ने हरी झंडी दिखाकर कारगिल जागरुकता रथ को रवाना किया । कारगिल पराक्रम से जुड़े चित्रों एवं अदम्य साहस का परिचय देने वाले कारगिल के परमवीरों की जानकारी से युक्त ये रथ लखनऊ शहर के विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर जाकर प्रचार–प्रसार करेंगे।इस अवसर पर केंद्रीय संचार ब्यूरो के निदेशक मनोज कुमार वर्मा ने बताया कि ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव, राइफलमैन संजय कुमार, कैप्टन मनोज कुमार पांडे और कैप्टन विक्रम बत्रा की शहादत की कहानी जानकर ही आने वाली पीढी उनसे प्रेरणा लेकर अपनी मातृभूमि के लिये सर्वस्व न्यौछावर करने को तैयार रहेगी । मुख्य समारोह का आयोजन फ्लोरेंस नाईटेंगल इंटर कॉलेज, त्रिवेणी नगर में 26 जुलाई को किया जायेगा।

विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने घेरी कोतवाली,

लापता लड़की की बरामदगी न होने पर जताई नाराजगी

उरई/जालौन। जालौन में 3 जुलाई को एक समुदाय का युवक दूसरे समुदाय की लड़की को भगाकर ले गया था। इस मामले में लड़की के पिता की मौत गई थी। जिस पर हिंदू संगठनों के साथ परिजनों ने बीते सप्ताह प्रदर्शन किया था। जिस पर पुलिस ने आश्वासन दिया था कि इस मामले में कार्रवाई की जाएगी और लड़की को बरामद कर लिया जाएगा। मगर एक सप्ताह से अधिक का समय बीत जाने के बावजूद भी अभी तक आरोपी की गिरफ्तारी न होने पर हिंदू संगठनों द्वारा प्रदर्शन किया गया और कोतवाली का घेराव किया गया। जिस पर पुलिस ने हिंदू संगठनों के लोगों को समझाकर शांत कराया और कार्रवाई का भरोसा दिया। मामला जालौन नगर कोतवाली का है। यहां 3 जुलाई को एक समुदाय का युवक दूसरे समुदाय की युवती को मंदिर से भगा ले गया था। जिस पर परिजनों ने युवक के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कराया था। इस घटना के बारे में लड़की के बीमार पिता को नहीं बताया था। जैसे ही उन्हें इसकी जानकारी हुई थी, 6 दिन बाद लड़की के पिता की मौत हो गई थी। जिस पर परिजनों ने बीते सप्ताह कोतवाली में हिंदू संगठनों के साथ प्रदर्शन किया था। जिस पर पुलिस ने और उप जिलाधिकारी ने आश्वासन दिया था कि युवती को बरामद कर लिया जाएगा। मगर अभी तक युवती को बरामद नहीं किया जा सका। न ही आरोपी युवक की गिरफ्तारी की गई। जिसको लेकर विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने जालौन कोतवाली का घेराव किया। पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस ने हिंदू संगठनों के लोगों को समझाने का प्रयास किया। इस दौरान मौके पर पहुंचे क्षेत्राधिकारी राम सिंह ने कहा कि जल्द से जल्द आरोपी की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। उसकी लोकेशन ट्रेस की जा रही है। साथ ही उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तब कहीं जाकर हिंदू संगठनों के लोग शांत हुए।

अधेड़ ने फांसी लगाकर दी जान,आर्थिक तंगी से था परेशान

उरई/जालौन। जालौन में संदिग्ध हालत में एक 42 वर्षीय ग्रामीण ने घर पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया। इस घटना को तब अंजाम दिया जब घर पर कोई नहीं था। पुत्र जैसे ही घर पर पहुंचा, उसने अपने पिता को फांसी पर झूलता देखा, उसकी चीख निकल गई। जिसको सुनकर पड़ोस के लोग मौके पर पहुंचे, जिन्होंने युवक को फांसी पर झूलता देखा, तत्काल पुलिस को सूचना दी। जानकारी मिलते ही कैलिया पुलिस फोरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंची। जिन्होंने जांच करने के बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया। वहीं आत्महत्या का कारण आर्थिक तंगी बताया जा रहा है। घटना कैलिया थाना क्षेत्र के ग्राम देवगांव की है। बताया गया कि यहां के रहने वाले धर्मेंद्र प्रजापति (42) पुत्र हरिराम ने बुधवार दोपहर को संदिग्ध हालत में अपने घर के कमरे में रस्सी का फंदा बनाकर फांसी लगा ली। जिससे दम घुटने से उसकी मौत हो गई। प्रभारी निरीक्षक राजीव बैस का कहना है इस मामले की जांच की जा रही है। वहीं पुत्र ने बताया कि पिता मजदूरी करते थे, आर्थिक तंगी की वजह से फांसी लगाई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है।

नौकरी दिलाने के नाम पर 27 लाख की ठगी,22 युवक हुए शिकार

बांदा। जनपद में जल जीवन मिशन योजना में नौकरी दिलाने के नाम पर 22 बेरोजगार युवकों से 27.70 लाख रुपए ठग लिए गए। ठगी के शिकार बने एक युवक ने मरका थाने में आरोपी के खिलाफ तहरीर दी है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें कि बेरोजगार युवकों को जल जीवन मिशन में नौकरी दिलाने का झांसा देकर एक ठग ने जनपद समेत आस पास के जिलों के 22 बेरोजगार युवकों से 27.70 लाख रुपए की ठगी कर ली। पारा बन्नो बेगम गांव निवासी रोहित सिंह ने मरका थाने में तहरीर देते हुए बताया कि एक व्यक्ति ने उसे बताया कि जल जीवन मिशन में अगर नौकरी चाहिए तो 1.20 लाख रुपए देना होगा। इसके अलावा फॉर्म का अलग से 8000 रुपए लगेगा और ठग के चंगुल में 22 बेरोजगार युवक फंस गए। सभी ने रुपए जमा कर दिए। फॉर्म भरने की औपचारिकता पूरी करने के बाद एग्रीमेंट भराया गया। एग्रीमेंट में आरोपी ने हस्ताक्षर किया और नियुक्त पत्र देते समय ठग ने उनके साथ फोटो भी खिंचवाई। नियुक्ति पत्र मिलने के बाद भी उसे नौकरी नहीं मिली तो लखनऊ में जल जीवन मिशन कार्यालय जाकर उसने जानकारी हासिल की, तभी विभागीय अधिकारियों ने नियुक्त पत्र को फर्जी बताया। फिर जाकर जालसाजी का खुलासा हुआ। युवक के मुताबिक ठगी के शिकार हुए युवकों में महेंद्र कुमार, आशीष सिंह, सचिन सिंह, बृजेंद्र सिंह, नितिन सिंह, कमलेश कुमार, दिनेश कुमार, सोनेलाल पटेल, संतोष कुमार, सत्येंद्र चक्रवर्ती, ऋषभ कुमार, शिव प्रकाश ज्ञान प्रकाश, संतोष राही, पुष्पेंद्र बाबू, अच्छे लाल आदि शामिल हैं। यह सभी बांदा समेत फतेहपुर और छतरपुर के निवासी हैं। उधर मरका थानाध्यक्ष उमेश कुमार ने बताया कि पारा बन्नो बेगम गांव निवासी ठगी का शिकार हुए युवक रोहित सिंह ने आरोपी के विरुद्ध थाने में तहरीर दी है। फिलहाल घटना की जांच–पड़ताल की जा रही है। जांच पूरी होने के बाद आरोपी के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की जाएगी।

कस्तूरबा विद्यालय की 8 छात्राओं की तबीयत बिगड़ी, मौसम खराब होने से हुई दिक्कत

उरई/जालौन। जालौन में उमस भरी गर्मी के कारण कस्तूरबा आवासीय विद्यालय गुढ़ा में पढ़ने वाली 8 छात्राओं की तबीयत बिगड़ गई। इसके बाद स्टाफ ने तत्काल छात्राओं को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जालौन में भर्ती कराया। जहां उनकी हालत देखते हुए डॉक्टरों ने इलाज शुरू कर दिया। ड्रिप चढ़ाने के बाद हालत में सुधार हुआ तो उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। मामला कस्तूरबा आवासीय बालिका विद्यालय गुढ़ा का है। यहां गर्मी के कारण विद्यालय में पढ़ने वाली छात्रा आस्था, आरती, ईशु, फरीदी, नविव्या, डॉली, सोनिया और रुचि की हालत बिगड़ गई। बच्चियों को उल्टी होने लगी। जिसे देखकर स्कूल स्टाफ ने तत्काल सभी बच्चियों को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया जहां डॉक्टरों ने इलाज के बाद अस्पताल भेज दिया। बताया जा रहा है कि स्कूल में लाइट न आने के कारण उमस भरी गर्मी में पंखे नहीं चल रहे थे। जिससे छात्राओं की तबीयत बिगड़ गई। प्रधानाचार्य गायत्री ने बताया कि की सभी बच्चियों की तबियत पानी गिरने के बाद उमस पड़ने के कारण हुई है। स्कूल में लाइट भी कम मिलती है इसलिए छात्राएं बीमार हुई है। बेसिक शिक्षा अधिकारी चंद्र प्रकाश का कहना है कि बच्चियों का इलाज करने के बाद तत्काल उन्हें छुट्टी दे दी गई। उनके स्वास्थ्य में सुधार है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, मौसम खराब होने के कारण उनकी तबीयत बिगड़ी थी।

बाढ़ से बचाव के लिए मॉक ड्रिल,नाविकों और गोताखोरों ने किया अभ्यास

बांदा। जिल में आज प्रशासन ने मॉक ड्रिल किया। ग्रामीणों को बाढ़ से निपटने और सावधानी बरतने का प्रशिक्षण भी दिया गया। बाढ़ के दौरान होने वाली मुश्किलों को कम समय में दूर करने के लिए प्रशासन में आवश्यक रिहर्सल भी किया। इस मौके पर ग्रामीणों को भरोसा दिलाया कि बाढ़ के दौरान उन्हें किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होने दी जाएगी। आपको बता दें कि बांदा की के नदी हर साल बाढ़ से होने वाले जान माल के नुकसान को देखते हुए जिला प्रशासन प्रदेश सरकार के निर्देश पर बाढ़ से निपटने के लिए साथ–साथ प्रभावित क्षेत्रों में कम जन धन की हानि हो इसके लिए तैयारी में जुट गई है। जिला प्रशासन की तरफ से बाढ़ से निपटने के लिए आज मॉक ड्रिल का आयोजन केन नदी के तट पर किया गया। इसमें अपर जिलाधिकारी राजेश कुमार, फायर सीओ मुकेश के साथ कई अधिकारी और नाविकों व गोताखोरों की पूरी टीम शामिल रही। बाढ़ से बचाव में उपयोग के लिए लाइफ सेविंग जैकेट, लाइफ ब्वॉय, मोटर बोट व नलवाड़ी के संचालन की जानकारी दी गई। मॉडल का प्रदर्शन करते हुए डूबते व्यक्ति को मोटर बोट से बचाकर उसे नदी से बाहर निकाल कर प्राथमिक उपचार लोगों के सामने किया गया। बाढ़ के दौरान विशेष सावधानी बरतने का सुझाव दिया गया, पानी यदि अधिक हो तो उसे पार करने की कोशिश ना करें, बल्कि दूसरे रास्ते से आवागमन करें। विद्युत तार यदि पानी में कहीं गिरा है, तो उस क्षेत्र से तुरंत चला जाना चाहिए। इसकी सूचना विद्युत विभाग या फिर उच्च अधिकारी को देनी चाहिए। घरों के आसपास विशेष सफाई रखें। जल भरा होने पर सांप बिछुआ अन्य जहरीले जंतु घर में घुस जाते हैं।

सपा नेता रामगोपाल यादव के करीबी रिश्तेदार पुष्पेंद्र को एसटीएफ ने उठाया, भेजा जेल

नोएडा,(यूएनएस)। सपा के वरिष्ठ नेता रामगोपाल यादव के करीबी रिश्तेदार जिला पंचायत सदस्य पुष्पेंद्र यादव को एसटीएफ ने नोएडा से गिरफ्तार कर लिया है। जिला पंचायत सदस्य पुष्पेंद्र यादव के ऊपर अलीगंज थाने में अपराध संख्या 294ध्21 धारा 395,307,354 में एफआईआर दर्ज थी। पुष्पेंद्र को गिरफ्तार करके अलीगंज कोतवाली लाया गया जहां से उसका चालान कर दिया। पुलिस के अनुसार फरार चलने की वजह से एटा पुलिस 25000 रुपए का इनाम घोषित किया था। उधर अलीगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर पुष्पेंद्र का मेडिकल कराया गया जहां से अदालत में पेश करने के लिए कड़ी सुरक्षा के बीच एटा भेज दिया गया। आप को बता दें कि पुष्पेंद्र यादव के पिता पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष जुगेंद्र सिंह यादव गैंगस्टर एक्ट में लगभग 16 माह से एटा जेल में बंद हैं। पुष्पेंद्र यादव के ताऊ अलीगंज से पूर्व विधायक रामेश्वर सिंह यादव गैंगस्टर एक्ट में लगभग 2 साल से अलीगढ़ जेल में बंद हैं। परिवार के अन्य सदस्यों की पुलिस को अभी तलाश है। रामेश्वर और जुगेंद्र पर 150 से भी अधिक मुकदमे दर्ज हैं। गौरतलब है कि पिछले दो वर्षों में तमाम मुकदमे दर्ज हुए हैं, जिनमें जमीनों पर अवैध कब्जा, दुष्कर्म, जानलेवा हमला, लूट जैसे मुकदमे शामिल हैं। करोड़ों की संपत्ति जब्त की जा चुकी है। दोनों भाइयों को भू माफिया घोषित किया जा चुका है। अपर पुलिस अधीक्षक धनंजय कुशवाह ने बताया जिला पंचायत सदस्य पुष्पेंद्र को गिरफ्तार किया गया है। उस पर 25 हजार रुपये का इनाम घोषित था। विधिक कार्रवाई के बाद उसे एटा जेल भेज दिया गया।

हिमेश रेशमिया ने नई फिल्म 'जानम तेरी कसम' का किया एलान, जानें कब होगी रिलीज

सिंगर, म्यूजिक डायरेक्टर और एक्टर हिमेश रेशमिया इंडस्ट्री का एक जाना–माना नाम है। उन्होंने बॉलीवुड में नाम कमाने के लिए लंबे समय तक संघर्ष किया है। वह उन सितारों में से एक हैं, जिन्होंने सिंगिंग के अलावा एक्टिंग में भी अपना जलवा बिखेरा। उन्होंने 23 जुलाई को अपना 51वां जन्मदिन सेलिब्रेट किया और देर रात नई फिल्म की घोषणा भी की।

हिमेश रेशमिया ने अपनी नई फिल्म 'जानम तेरी कसम' लेकर आ रहे है। सिंगर ने फिल्म के ऐलान के साथ–साथ इसका एक पोस्टर और सॉन्ग टीजर भी जारी किया। इसके अलावा, फिल्म की रिलीज डेट से भी पर्दा उठाया। यह फिल्म 2025 में दशहरे के मौके पर रिलीज होगी।फिल्म का टाइटल ट्रैक शेयर करते हुए हिमेश ने इंस्टा पर एक और पोस्ट शेयर किया, इस पर रील्स बनाने की अपील की। उन्होंने कैप्शन में लिखा, "'जिस दर्द में आराम है, इश्क उसी का नाम है''जानम तेरी कसम' के टाइटल ट्रैक पर अपनी खुद की रील बनाएं'। हिमेश ने अपने पोस्ट को कैप्शन दिया, 'जन्मदिन की शुभकामनाओं के लिए बहुत–बहुत धन्यवाद! 'जानम तेरी कसम' एक दर्दभरी प्रेम कहानी है। राव और सप्रू फिल्म्स के सहयोग से हिमेश रेशमिया मेलोडीज द्वारा निर्मित यह फिल्म दशहरा 2025 पर रिलीज होगी। इस फिल्म को राधिका राव और विनय सप्रू डायरेक्ट करेंगे।सिंगर के करियर की बात करें तो हिमेश रेशमिया ने म्यूजिक डायरेक्टर के तौर पर 1998 में 'प्यार किया तो डरना क्या' से अपने करियर की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने कई फिल्मों में संगीत दिया, जिसमें 'हेलो ब्रदर', 'दुल्हन हम ले जाएंगे', 'बंधन' और 'तेरे नाम' शामिल हैं। 'झलक दिखला जा', 'आशिक बनाया आपने', 'आप की कशिश', 'नाम है तेरा तेरा' जैसे कई हिट गानों के जरिए उन्होंने लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई। हिमेश ने एक्टिंग में भी किस्मत आजमाई। उन्होंने साल 2007 में फिल्म 'आप का सुरूर' से बॉलीवुड में एक्टिंग करियर की शुरुआत की। इसके बाद वह फिल्म 'कर्ज' में नजर आए। उन्होंने 'रेडियो', 'कजरारे', 'दमादम', 'द एक्सपॉज', 'तेरा सुरूर', 'खिलाड़ी 786' और 'हैप्पी हार्डी एंड हीर' जैसी फिल्मों में काम किया। वह जल्द ही 'बडास रवि कुमार' और 'जानम तेरी कसम' में नजर आएंगे।

डीएम ने ओवरलोड वाहनों पर कड़ी कार्रवाई के दिए निर्देश,

अधिकारियों के साथ की जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक

नोएडा। नोएडा में सड़क दुर्घटना पर शत प्रतिशत अंकुश लगाने एवं सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु दर को कम करने तथा यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने अधिकारियों के साथ एक बैठक की। बैठक के दौरान परिवहन विभाग व पुलिस विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने परिवहन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि उनके द्वारा जनपद में बस, टेंपो एवं टैक्सी स्टैंड के निर्माण के लिए गंभीरता के साथ कार्रवाई करते हुए स्थलों को चिन्हित कर प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। ताकि अवैध स्टैंड, अतिक्रमण पर अंकुश लगाया जा सके। उन्होंने परिवहन एवं पुलिस विभाग के अधिकारियों को कहा कि उनके द्वारा नियमित रूप से अभियान चलाकर अवैध स्टैंड, अवैध पार्किंग, ओवरस्पीड, ओवरलोड वाहन एवं यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाए। संबंधित विभागीय अधिकारियों के द्वारा जनपद में जो भी ब्लैक स्पॉट बने हुये हैं, उनमें अधिकारी आपसी सामंजस्य स्थापित कर प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए ब्लैक स्पॉट को कम करने की दिशा में अपनी–अपनी कार्यवाही करें। उन्होंने सभी सम्बन्धित विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनपद के ब्लैक स्पॉट स्थल का संयुक्त निरीक्षण करते हुए ब्लैक स्पॉट को खत्म करने के लिए कार्ययोजना तैयार करें। उन्होंने परिवहन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि उनके द्वारा शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ आपसी समन्वय स्थापित करते हुए जनपद के समस्त विद्यालयों में विद्यालय यान सुरक्षा के तहत स्कूलों में अभियान चलाकर स्कूल वाहनों की फिटनेस जांच अवश्य करा ली जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि बिना फिटनेस के स्कूली बस सड़कों पर न उतर पाए। उन्होंने प्राधिकरणों एवं लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों से कहा कि उनके द्वारा आपसी समन्वय स्थापित करते हुए जनपद में टूटी हुई सड़कों के मरम्मत कार्य कराए जाने की प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। इस दौरान नोएडा ट्रांसपोर्ट यूनियन के सदस्यों के द्वारा जिलाधिकारी को जनपद में बाहर से आने वाली ओवरलोड गाड़ियों के संबंध में अवगत कराया गया, जिस पर जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनपद में अभियान चलाकर एक सप्ताह के अंदर ओवरलोड गाड़ी और यातायात का उल्लंघन करने वालों वाहनों पर जुर्माना लगाते हुए सख्त कार्रवाई की जाए। बैठक में डीसीपीटी ट्रैफिक यमुना प्रसाद, सीडीओ जनार्दन सिंह, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व अतुल कुमार, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी प्रवर्तन सियाराम वर्मा, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी प्रशासन विपिन चौधरी, अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग कंचन सिंह वर्मा, जिला विद्यालय निरीक्षक डॉ धर्मवीर सिंह, बेसिक शिक्षा अधिकारी राहुल पवार आदि मौजूद रहे।

अक्षय कुमार ने किया चौंकाने वाला खुलासा, 'धोखाधड़ी' के हो चुके हैं शिकार, कहा- 'चुप रह जाता हूं'

बॉलीवुड में हर साल की फिल्में रिलीज होती हैं, जिसमें से कई फिल्में चलती हैं तो कई फिल्में पिट जाती हैं। कई सितारे बैक टू बैक हिट देते हैं तो वहीं के नसीब में बैक टू बैक फ्लॉप फिल्में भी आती हैं। अक्षय कुमार भी एक ऐसे एक्टर हैं जो हर साल कई फिल्में लेकर आते हैं। बीता साल एक्टर के लिए खासा अच्छा नहीं रहा और इस साल की शुरुआत भी काफी लो रही। साल 2024 में अक्षय कुमार अब तक दो फिल्मों के साथ आए। बिग बजट फिल्म 'बड़े मियां छोटे मियां' पर्दे पर रिलीज हुई और बुरी तरह पिट गई। इसके चंद महीने बाद ही 'सरफिरा' रिलीज हुई। इस फिल्म को क्रिटिक्स ने सराहा और कहा कि कंटेंट कुमार की वापसी हो गई है, लेकिन फिर भी इस फिल्म को दर्शकों का प्यार नहीं मिला। कमाई के मामले में ये फिल्म भी फिसड्डी साबित हुई और इसी के साथ ही साल 2024 की फिल्मी शुरुआत कुछ खास नहीं रही। अब अक्षय कुमार अपनी तीसरी फिल्म के साथ आ रहे हैं।

फिल्मों की रिलीज के बीच ही अक्षय कुमार इनके प्रमोशन्स में भी लग हुए हैं। 'सरफिरा' की रिलीज के बाद भी एक्टर फिल्म को प्रमोट कर रहे हैं और इसी बीच उन्होंने 'सरफिरी बातें' नाम का एक चौट शो शुरू किया है, जिसमें वो फेमस लोगों के साथ पॉडकास्ट सेशन कर रहे हैं। हाल में ही अक्षय कुमार ने बिजनेसवुमन गजल अलघ से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने बताया कि जिंदगी में कई बार ऐसे मौके आए जब वो ठगे गए और उन्हें इससे काफी हताशा और निराशा भी हुई। काम के बाद पेमेंट न मिलने की भी उन्होंने बात बताई।

अक्षय कुमार ने यूट्यूब पर गजल अलघ से बात करते हुए कई खुलासे किए हैं। सरफिरी बातें के एक एपिसोड में अक्षय ने बताया कि उन्हें कई बार ठगी का अहसास हुआ। खास तौर पर तब जब उनकी फिल्मों के प्रोड्यूसर काम कराने के बाद पैसे नहीं देते थे। अक्षय कुमार ने ठगा महसूस करने की बात कहते हुए कहा, 'एक दो प्रोड्यूसर की पेमेंट नहीं आती है और यह सीधा धोखा है, ठगी है।' इसी कड़ी में आगे बात करते हुए खिलाड़ी कुमार ने बताया कि वो इन परिस्थितियों से किस तरह डील करते हैं। अक्षय कुमार ने कहा कि वह ऐसे व्यक्ति से अलग हो जाते हैं जो उनके साथ धोखा करता है। अक्षय कहते हैं, 'उसके बाद मैं उससे बात ही नहीं करता, चुप हो जाता हूं अपने साइड में निकल जाता हूं।'

बता दें, जल्द ही अक्षय कुमार नई फिल्म 'खेल खेल में' में नजर आएंगे। ये फिल्म 15 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। इस फिल्म में तापसी पन्नु, एमी विर्क, फरदीन खान, वाणी कपूर, आदित्य सील और प्रज्ञा जैसवाल किरदार हैं। इस फिल्म के अलावा अक्षय कुमार की पाइपलाइन में 'सिंघम अगेन', 'वेलकम टू द जंगल', 'हेरा फेरी 3' जैसी कई फिल्में हैं।

मन्नत मांगने पंचकूला के श्री नाडा साहिब गुरुद्वारा पहुंची शिवांगी जोशी, शेयर की फोटो

शिवांगी जोशी टीवी इंडस्ट्री का जाना–पहचाना नाम है। अपनी शूटिंग शेड्यूल से वक्त निकालकर वह पंचकूला के नाडा साहिब गुरुद्वारा में दर्शन करने पहुंचीं। एक्ट्रेस ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम के स्टोरीज सेक्शन में फोटो का एक कोलाज शेयर किया।शिवांगी ने कोलाज में गुरुद्वारे की फोटोज और एक सेल्फी शेयर की, जिसमें वह अपने करीबी साथियों के साथ लाल दुपट्टा सिर पर ओढ़े नजर आ रही हैं। एक्ट्रेस के बारे में बात करें तो, शिवांगी ने 2013 में श्वेलती है जिंदगी आंख मिचोलीश से एक्टिंग करियर की शुरुआत की, जहां उन्होंने त्रिशा का किरदार निभाया। इसके बाद उन्होंने बेइंतहा में आयत हैदर का किरदार निभाया। 2014 में, वह लव बाय चांस में विशी के रूप में दिखाई दीं। लेकिन पहचान विशाल आदित्य सिंह और श्वेता तिवारी के शो बेगूसराय से मिली, जिसमें एक्ट्रेस ने पूनम ठाकुर का रोल अदा किया। इस किरदार के लिए उन्हें फ्रेश न्यू फेस– फीमेल के लिए इंडियन टेली अवार्ड में नॉमिनेशन मिला। 2016 में, वह ये है आशिकी के सीजन 4 में मीरा के किरदार में दिखाई दीं। स्टार प्लस का हिट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में नायरा सिंघानिया गोयनका का किरदार निभाकर उन्होंने लाखों दर्शकों के दिल में खास जगह बनाई। उनकी केमिस्ट्री को मोहसिन खान के साथ खूब सराहा गया। ये रिश्ता क्या कहलाता है के अलावा प्यार तूने क्या किया में भी दिखाई दीं। हाल ही में, एक्ट्रेस ने कुशाल टंडन के साथ बरसातें–मौसम प्यार का में काम किया। इसके अलावा, शिवांगी वेब सीरीज जब वी मैच्ड का हिस्सा रही हैं और स्टंट–बेस्ड रियलिटी शो फियर फैक्टर खतरों के खिलाड़ी 12 में भी नजर आई थीं।

गोवा में होने वाले इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के डायरेक्टर बने शेखर कपूर

मशहूर फिल्म निर्देशक शेखर कपूर को गोवा में आयोजित होने वाले इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल (आईएफएफआई) के 55वें और 56वें एडिशन के लिए फेस्टिवल डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है। इसकी जानकारी सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने दी। बता दें कि आईएफएफआई के 54वें एडिशन का आयोजन पिछले साल 20 से 28 नवंबर के बीच किया गया था। तब के केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने इस 8 दिवसीय समारोह का उद्घाटन किया था। इस दौरान गोवा के मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत भी मौजूद रहे।

इवेंट की शुरुआत करते हुए एक्ट्रेस नुसरत भरूचा ने फिल्म पुष्पा के सामी–सामी गाने पर परफॉर्म किया था। वहीं माधुरी दीक्षित ने ओरे पिया, घर मोरे परदेसिया, डोला रे और आजा नाच ले जैसे हिट गानों पर डांस किया। वहीं शाहिद कपूर ने भी नगाड़ा, सज–धज के, साड़ी के फॉल सा जैसे सुपरहिट गानों पर डांस कर दर्शकों का उत्साह बढ़ाया।

इवेंट में 270 फिल्मों का प्रसारण हुआ था। पिछले बार के सेलिब्रेशन को देख दर्शक अब इस अपकमिंग इवेंट को लेकर काफी एक्साइटेड हैं। शेखर कपूर की बात करें तो उन्होंने इंडस्ट्री में कई सुपरहिट फिल्में दी। साल 1975 में फिल्म जान हाजिर है से उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की। वह फूलन देवी की बायोपिक बैंडिट क्वीन बनाने को लेकर चर्चाओं में आए। इसके लिए उन्होंने कई अवॉर्ड्स अपने नाम किए। कान फिल्म फेस्टिवल और एडिनबर्ग फिल्म फेस्टिवल में बैंडिट क्वीन का प्रीमियर किया गया। उन्हें एलिजाबेथ, एलिजाबेथ द गोल्डन एज, द फोर फीदर्स, मासूम, मिस्टर इंडिया और व्हॉट्स लव गॉट टू डू विद इट जैसी फिल्मों के बेहतरीन निर्देशन के लिए जाना जाता है। वर्कफ्रंट की बात करें तो वह अब मासूम के सीक्वल की तैयारी कर रहे हैं। इसका टाइटल मासूम...द नेक्स्ट जेनरेशन तय किया गया है। बता दें कि मासूम में लीड एक्टर के तौर पर नसीरुद्दीन शाह ने काम किया था। यह 1983 में रिलीज हुई थी।

अवध की आवाज हिन्दी दैनिक, प्रकाशक ,मुद्रक व स्वामी,अनिल कुमार सिंह द्वारा स्काई लाइन प्रिन्टर्स,119/23 खन्दारी लेन, लालबाग, लखनऊ उ0प्र0 से मुद्रित तथा डी–97/3 व 7,सैक्टर–7, इन्दिरा नगर,लखनऊ,उ0प्र0 से प्रकाशित। सम्पादक अनिल कुमार सिंह फोन : 0522–4340954 मो0–7905407289, Email: avadhkiaawaz@gmail.com
R.N.I.- UPHIN/2012/45127
नोट : समाचार पत्र से सम्बंधित सारे विवादोंका न्याय क्षेत्र लखनऊ होगा।